● वर्ष : 17 ● अंक : 258 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

WWW.LKSTV.IN

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित बुधवार 08 जुलाई 2026

भारत-इंडोनेशिया के बीच रक्षा, ब्रह्मोस, अंतरिक्ष और डिजिटल सहयोग समेत 14 समझौते

एजेंसी। जकार्ता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली, अंतरिक्ष, दूरसंचार, स्वास्थ्य, कृषि, खनिज, आपदा प्रबंधन और चुनावी सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 14 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, डिजिटल कॉमर्स, प्रबंधन शिक्षा और खाद्य सुरक्षा समेत छह नई पहलों की भी घोषणा की, जिससे द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज एवं उपयोग संबंधी सहयोग समझौते का विस्तार, भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और इंडोनेशिया की औषधि एवं खाद्य नियामक एजेंसी (बीपीओएम) के बीच चिकित्सा उत्पादों के विनियमन में सहयोग, खनिज एवं इस्पात आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग संबंधी समझौते शामिल हैं। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा सहयोग संबंधी समझौते का विस्तार, भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के बीच सहयोग, दूरसंचार प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार तथा स्वास्थ्य कार्यबल सहयोग से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और इंडोनेशिया के जनरल इलेक्शन कमीशन (केपीयू) के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देते हुए ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली पर सहयोग तथा एयर-टू-एयर मिसाइल सहयोग समझौता भी किया गया। औद्योगिक सहयोग के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) और इंडोनेशिया की पीटी क्राकाताउ स्टील के बीच इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए रणनीतिक संयुक्त उपक्रम पर सहमति बनी। वहीं, भारत के नॉन-फेरस मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (एनएफटीडीसी), मिडवेस्ट लिमिटेड और पीटी पर्मिनास के बीच रेयर अर्थ मैग्नेट के विकास के लिए भी समझौता हुआ। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने छह महत्वपूर्ण नई पहलों की भी घोषणा की। इनमें योग्यकार्ता स्थित ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण एवं पुनरुद्धार में भारत की ओर से सहायता, हिंद महासागर क्षेत्र के सूचना संलयन केंद्र (आईएफसी-आईओआर) में इंडोनेशियाई संपर्क अधिकारी की तैनाती तथा इंडोनेशिया को 100 टन उच्च गुणवत्ता वाले डीडब्ल्यूआर-162 गेहूं के बीज उपलब्ध कराना शामिल है।

कई नई पहल की घोषणा

प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता, व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गति देने पर सहमति

जकार्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच मंगलवार को हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और महत्वपूर्ण खनिजों सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान इस्ताना मर्देका (राष्ट्रपति भवन) में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका औपचारिक स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। जनवरी 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की भारत यात्रा के बाद दोनों नेताओं की यह पहली द्विपक्षीय बैठक थी। दोनों नेताओं के बीच सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमें व्यापार एवं निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा, समुद्री सहयोग, डिजिटल और वित्तीय प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं औषधि, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज एवं रेयर अर्थ, संस्कृति, पर्यटन, कृषि तथा जन-से-जन संपर्क सहित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) की तर्ज पर इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क (आईओएन) की शुरुआत का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2027 में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से 'टैगोर-देवांतरा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कूटनीति वर्ष' मनाने की घोषणा भी की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया तथा आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने मुक्त, खुला और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के 'महासागर' (म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन) दृष्टिकोण की भी जानकारी दी। राष्ट्रपति प्रबोवो ने वर्ष 2026 में ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

भारत और इंडोनेशिया के लिए कई क्षेत्रों में असीमित अवसर : मोदी

एजेंसी। जकार्ता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के लिए अनेक क्षेत्रों में असीम अवसर मौजूद हैं और तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार अब और टाला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि दोनों देश स्वाभाविक साझेदार हैं और भारत उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में इंडोनेशिया को हरसंभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज वैश्विक व्यवस्था तेजी से बदल रही है और भारत एवं इंडोनेशिया जैसे विकासशील देश समान भागीदारी और अधिक भूमिका की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया में अब और देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि वैश्विक संस्थाएं वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित कर सकें। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया भविष्य के स्वाभाविक साझेदार हैं तथा दोनों देशों के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और सामरिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत इंडोनेशिया को उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए तैयार है और अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त, खुला और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र का प्रबल समर्थक है तथा समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति पूरी तरह आसियान केंद्रित है और आसियान की केंद्रीय भूमिका भारत की इंडो-पैसिफिक नीति का आधार है। आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इंडोनेशिया ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई, जिसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को और मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' है, जबकि इंडोनेशिया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

संक्षिप्त समाचार

ब्रिक्स महिला मंत्रीस्तरीय बैठक की 8-9 जुलाई को, भारत करेगा मेजबानी

नई दिल्ली। भारत 8-9 जुलाई को केरल के कोच्चि में ब्रिक्स महिला मंत्रीस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। यह बैठक इस साल भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हो रही है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख शामिल होंगे, जो महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और समावेशी, लचीले तथा सतत विकास के साझा संकल्प को दोहराएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता चार स्तंभ लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स महिला ट्रैक को इन्हीं आयामों में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए संरचित किया गया है। यह बैठक 6-7 जुलाई को हुई ब्रिक्स महिला कार्य समूह बैठक के बाद आयोजित की जा रही है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने प्राथमिक क्षेत्रों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। मंत्रीस्तरीय बैठक में प्रस्तावित परिणामों पर चर्चा होगी और सदस्य देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक दिशा तय की जाएगी। बैठक में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने, आर्थिक अवसरों का विस्तार करने, डिजिटल और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा जलवायु कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं के योगदान को मान्यता देने पर उच्चस्तरीय संवाद होगा।

होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर लगेगा शुल्क, भारत को राहत!

नई दिल्ली । ईरान ने संकेत दिया है कि भविष्य में होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से सेवा शुल्क लिया जा सकता है। हालांकि, तेहरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि मित्र देशों के लिए विशेष रियायत पर विचार किया जाएगा। इस बयान के बाद दुनिया के कई देशों की नजर इस फैसले पर टिक गई है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का प्रमुख समुद्री मार्ग माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लागू भी करता है, तो भारत को मित्र देश का दर्जा मिलने के कारण विशेष छूट या रियायत मिल सकती है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम स्थिति ईरान की आधिकारिक नीति और आगामी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। चीन में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ईरान के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य का एक हिस्सा ईरान के क्षेत्रीय जल में आता है। ऐसे में वहां से गुजरने वाले जहाजों से सेवा शुल्क लेना स्वाभाविक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे पारंपरिक टोल टैक्स के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि समुद्री सेवाओं से जुड़े शुल्क के तौर पर समझा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन देशों ने कठिन समय में ईरान का साथ दिया है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है।

नड्डा ने केरल के स्वास्थ्य तंत्र को और मजबूत बनाने का दिया आश्वासन

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मंगलवार को केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन के साथ आभासी बैठक कर राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं एवं जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। नड्डा ने केरल सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान, मुफ्त दवा सेवा पहल, मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवा पहल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य मानव संसाधन, चिकित्सा शिक्षा, औषधि नियमन तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने, गुणवत्तापूर्ण दवाओं एवं जांच सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने, स्वास्थ्य अवसंरचना और मानव संसाधन को मजबूत करने, चिकित्सा शिक्षा में सुधार, दवाओं एवं ब्लड बैंकों की नियामक व्यवस्था को सशक्त बनाने तथा राज्य में खाद्य सुरक्षा प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। मुरलीधरन ने विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में राज्य की प्रगति की जानकारी दी।

डूरंड कप युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को नई पहचान देगा : राष्ट्रपति

एजेंसी। नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट-2026 की ट्रॉफियों का अनावरण और उन्हें रवाना करते हुए कहा कि भारत को वैश्विक फुटबॉल जगत में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डूरंड कप जैसे ऐतिहासिक टूर्नामेंट देश में फुटबॉल की नई प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने डूरंड कप टूर्नामेंट-2026 की ट्रॉफियों का अनावरण एवं फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने डूरंड कप से जुड़े वर्तमान और पूर्व अधिकारियों तथा खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता ने वर्षों से अनेक प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ियों को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मंच उपलब्ध कराया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष डूरंड कप, प्रेसिडेंट्स कप और शिमला ट्रॉफी के लिए कुछ नई टीमें भी प्रतियोगिता में भाग लेंगी, जिनमें श्रीलंका की एक टीम भी शामिल है। नई टीमों के शामिल होने से इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की लोकप्रियता और बढ़ेगी। राष्ट्रपति ने सभी भाग लेने वाली टीमों और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। डूरंड कप के मैच इस बार कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलांग के साथ-साथ पहली बार रांची में भी आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि फुटबॉल दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है और यह उत्कृष्टता, एकता तथा खेल भावना का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहे फीफा विश्व कप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें और खिलाड़ी अपने-अपने देशों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों के दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसक हैं और उनका शानदार प्रदर्शन खेल प्रेमियों को प्रेरित करता है। फुटबॉल लोगों को जोड़ने का माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि खेल भावना केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की प्रेरणा देती है। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जिस प्रकार फुटबॉल खिलाड़ी जीत के लिए एक-दूसरे का साथ देते हैं, उसी प्रकार देशवासी भी एकजुट होकर विकसित भारत के संकल्प को अवश्य साकार करेंगे।

पीएम-सेतु योजना के तहत 1,237.58 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (पीएम-सेतु) योजना का देशभर में विस्तार किया जाएगा। इसके तहत ओडिशा, गुजरात और तेलंगाना में औद्योगिक साझेदारी आधारित आईटीआई उन्नयन के लिए कुल 1,237.58 करोड़ रुपये की रणनीतिक निवेश योजनाओं (एसआईपी) को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में आयोजित पीएम-सेतु की चौथी राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में महानिदेशक (प्रशिक्षण) दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक शामिल हुए। समिति ने पीएम-सेतु को पायलट चरण से आगे बढ़ाते हुए देशभर के 200 चिह्नित आईटीआई क्लस्टरों में लागू करने की मंजूरी दी। साथ ही योजना के क्रियान्वयन को सरल बनाने, उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने, सार्वजनिक उपक्रमों को जोड़ने और संस्थागत सहयोग को मजबूत करने के उपायों को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में ओडिशा के लिए 240.21 करोड़ रुपये की निवेश योजना को मंजूरी दी गई।

राम मंदिर ट्रस्ट ने सार्वजनिक किया आय-व्यय का पूरा ब्यौरा

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोपों के बीच पहली बार अपने वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए हैं। ट्रस्ट ने दान, खर्च और कीमती धातुओं के उपयोग का एक विस्तृत ब्यौरा जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उसके गठन के बाद से प्राप्त हर एक रुपये का हिसाब दर्ज है। ट्रस्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी श्रद्धालु अपने दान के सत्यापन के लिए इसकी जांच करा सकता है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन के मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) लगातार कार्रवाई कर रहा है। जांच एजेंसियां नकदी, दान पेटियों, सोना-चांदी, विदेशी मुद्रा और अन्य वित्तीय लेन-देन की गहन जांच में जुटी हैं, और अब तक इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रस्ट के अनुसार, उसके गठन के बाद से उसे कुल 3,264 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसमें निधि समर्पण अभियान, कॉर्पस फंड, देश-विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान और अन्य स्वैच्छिक योगदान शामिल हैं।

ज्वलंत मुद्दा संपादकीय

बांग्लादेश की बदलती सैन्य सोच और भारत के सामने नई सुरक्षा चुनौती

भारत और बांग्लादेश के संबंध दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारियों में गिने जाते रहे हैं। वर्ष 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय में भारत की निर्णायक भूमिका रही थी। दोनों देशों ने दशकों तक सुरक्षा, व्यापार, जल बंटवारे, सीमा प्रबंधन और सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में उल्लेखनीय सहयोग किया। किंतु पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति, उसकी सैन्य सोच और विदेश नीति में दिखाई दे रहे बदलावों ने नई चिंताओं को जन्म दिया है। विशेष रूप से बांग्लादेशी सेना में धार्मिक प्रतीकों और इस्लामी पहचान को अधिक प्रमुखता देने की खबरों ने भारत सहित पूरे क्षेत्र का ध्यान आकर्षित किया है।

हाल के घटनाक्रमों के अनुसार बांग्लादेशी सेना की कुछ नई बटालियनों का नाम इस्लामी इतिहास के शुरुआती खलीफाओं के नाम पर रखा गया है और सेना के पारंपरिक राष्ट्रवादी नारों के स्थान पर धार्मिक नारों को महत्व दिए जाने की चर्चा भी सामने आई है। यदि यह प्रवृत्ति आगे बढ़ती है तो यह केवल सैन्य परंपरा का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश की बदलती वैचारिक दिशा का संकेत भी माना जाएगा। किसी भी सेना का चरित्र केवल उसके हथियारों से नहीं, बल्कि उसके मूल्यों, प्रतीकों और प्रशिक्षण से भी निर्धारित होता है।

शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की राजनीति में इस्लामी संगठनों और धार्मिक समूहों का प्रभाव बढ़ने की चर्चा लगातार हो रही है। लंबे समय तक अवामी लीग ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद और जय बांग्ला की भावना को राष्ट्रीय पहचान का आधार बनाया था। अब यदि सेना के भीतर धार्मिक पहचान को अधिक महत्व दिया जा रहा है तो यह उस वैचारिक परिवर्तन का हिस्सा माना जा सकता है जो देश की राजनीति और समाज में भी दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की इस बदलती सोच के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण घरेलू राजनीति है। किसी भी देश की सरकार और सत्ता प्रतिष्ठान अपने समर्थक सामाजिक वर्गों को संतुष्ट करने के लिए कई बार सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते हैं। यदि इस्लामी संगठनों का प्रभाव बढ़ता है तो सेना सहित अन्य संस्थाओं पर भी उसका प्रभाव दिखाई देना स्वाभाविक माना जाता है।

दूसरा कारण क्षेत्रीय शक्ति संतुलन है। बांग्लादेश आज चीन और पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। रक्षा उपकरणों की खरीद, सैन्य प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास इसी रणनीति का हिस्सा माने जाते हैं। इससे वह अपने रक्षा विकल्पों को व्यापक बनाना चाहता है ताकि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता न रहे।

तीसरा कारण भारत के साथ कुछ पुराने और नए विवाद भी हैं। सीमा पर अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, जल बंटवारा, व्यापारिक असंतुलन तथा राजनीतिक बयानबाजी जैसे मुद्दों ने समय-समय पर दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया है। बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक और धार्मिक समूह भारत विरोधी भावनाओं को घरेलू राजनीति में समर्थन जुटाने के लिए भी इस्तेमाल करते रहे हैं। हालांकि यह कहना उचित नहीं होगा कि पूरा बांग्लादेश या उसकी पूरी जनता भारत विरोधी है। वहां बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक, बुद्धिजीवी और व्यापारी भी हैं जो भारत के साथ अच्छे संबंधों को अपने देश के हित में मानते हैं।

भारत के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा का है। यदि भारत-बांग्लादेश सीमा के निकट सैन्य गतिविधियां बढ़ती हैं या सीमा क्षेत्रों में तनाव का वातावरण बनता है तो उसका सीधा प्रभाव असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर पड़ सकता है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

पर्यावरण संतुलन की चिंता किए बिना विकास बेमानी दिल्ली के रिज को फिर से हरा-भरा बनाएंगे : शाह

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि पर्यावरण संतुलन की चिंता किए बिना विकास का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 6,300 हेक्टेयर ग्रीन रिज क्षेत्र को फिर से हराभरा बनाने के लिए अगले चार वर्षों में एक करोड़ से अधिक देशी पौधे लगाए जाएंगे और पूरे रिज को दिल्ली के 'हरे फेफड़ों' के रूप में विकसित किया जाएगा। शाह ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत दिल्ली में 'मिशन 70 लाख' पौधारोपण अभियान का शुभारंभ औरा दिल्ली सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य दिल्ली के रिज क्षेत्र के पुनर्जीवन का संकल्प लेना है। रिज को फिर से कानूनी संरक्षण प्रदान करने, उसकी जैव विविधता बहाल करने, मिट्टी एवं जल संसाधनों का संरक्षण करने तथा दिल्ली के पर्यावरण को नया जीवन देने का अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों में पूरे रिज क्षेत्र में पीपल, बरगद, नीम, गूलर, अर्जुन और जामुन जैसे दीर्घायु देशी वृक्ष लगाए जाएंगे, जो 100 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा एक करोड़ से अधिक देशी पौधों के साथ 35 लाख बड़े वृक्षों तथा 65 लाख झाड़ियों, बांस और औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा। गृहमंत्री ने कहा कि वर्ष 1994 में दिल्ली के 7,784 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था, लेकिन इसकी अंतिम अधिसूचना तीन दशक से लंबित थी। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि अब 5,000 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और शेष क्षेत्र को भी कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रिज क्षेत्र में बड़ी संख्या में जहरीले बबूल और अन्य कंटीले वृक्ष हैं, जो हरियाली का भ्रम तो पैदा करते हैं, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी नहीं हैं। इनके स्थान पर देशी प्रजातियों के वृक्ष लगाए जाएंगे, जिससे जैव विविधता और प्राकृतिक पारिस्थितिकी को मजबूती मिलेगी।

संक्षिप्त समाचार

जहांगीरपुरी हिट एंड रन केसः मर्सिडीज चालक गिरफ्तार

लोकतंत्र की शानः नई दिल्ली। उत्तर पश्चिमी जिले के जहांगीरपुरी इलाके में हुए हिट एंड रन मामले में पुलिस ने फरार मर्सिडीज चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी, पीसीआर कॉल और वाहन के पंजीकरण संबंधी जानकारी के आधार पर आरोपित की पहचान कर उसे दबोच लिया।उत्तर पश्चिमी जिले की पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने मंगलवार को बताया कि 5 जुलाई को जहांगीरपुरी थाना पुलिस को आउटर रिंग रोड (जीटीके बाईपास) पर जहांगीरपुरी बस स्टैंड के पास फुटओवर ब्रिज के निकट सड़क हादसे की सूचना मिली। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल मिला, जिसे तुरंत बाबू जगजीवन राम मेमोरियल (बीजेआरएम) अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में मृतक की पहचान मंगोलपुरी निवासी दीपक के रूप में हुई। जांच के दौरान पुलिस को पीसीआर कॉल करने वाले प्रत्यक्षदर्शी से महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसने बताया कि एचआर-51बीटी-6304 नंबर की मर्सिडीज कार ने स्कूटी को टक्कर मारी थी और चालक मौके से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने वाहन का पता लगाकर उसके पंजीकृत मालिक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 133 के तहत नोटिस जारी किया। पूछताछ में सामने आया कि हादसे के समय कार अंश प्रताप सिंह चला रहा था। साक्ष्यों के आधार पर जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने एफआईआर संख्या 436/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 और 106(1) में मामला दर्ज कर आरोपित चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

सीजीपी का 'एक्स' अकाउंट होगा बहाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश

लोकतंत्र की शानः नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजीपी) का 'एक्स' अकाउंट बहाल करने का आदेश दिया है। मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी का 'एक्स' अकाउंट बहाल करने पर कोई आपत्ति नहीं है।इंटेलिजेंस ब्यूरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से 'एक्स' अकाउंट ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'एक्स' को कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया था। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का 'एक्स' अकाउंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के आधार पर ब्लॉक किया गया था। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 'एक्स' अकाउंट ब्लॉक करने के फैसले को चुनौती की थी। इस पर कोर्ट ने 29 मई को केंद्र और 'एक्स' को नोटिस जारी किया था।दरअसल, 15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा था कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसे कई बेरोजगार युवा जिन्हें न तो रोजगार मिलता है और न ही पेशे में कोई ठिकाना तो वे आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट या अन्य तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और पूरे सिस्टम पर हमला करने लग जाते हैं। कोर्ट ने कहा था कि कुछ वकीलों खासकर दिल्ली में लॉ डिग्रियों की प्रामाणिकता की सीबीआई जांच की जरुरत है। बाद में मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले पर सफाई भी दी। सफाई में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुझे यह पढ़कर दुख हुआ कि मीडिया के एक हिस्से ने एक तुच्छ मामले की सुनवाई के दौरान मेरी मौखिक टिप्पणियों को किस तरह गलत तरीके से पेश किया है। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी, जिन्होंने फर्जी और नकली डिग्रियों की मदद से वकालत जैसे व्यवसायों में प्रवेश किया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायों में भी घुसपैठ कर चुके हैं और इसलिए, वे परजीवी की तरह हैं।मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के रुप में ऑनलाइन आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर देखते ही देखते काफी लोकप्रियता मिली। इसी के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना शुरू किया गया, जो अभी भी चल रहा है।

कांग्रेस ने कोरोहेल्थ में 900 कर्मचारियों की छंटनी पर लेबर कोड को बताया मजदूर विरोधी

लोकतंत्र की शानः नई दिल्ली। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अमेरिका की हेल्थकेयर एनालिटिक्स कंपनी कोरोहेल्थ द्वारा केरल के कोच्चि और कोझिकोड स्थित ब्रांच में करीब 900 मेडिकल कर्मचारियों की अचानक छंटनी को मजदूर वर्ग के लिए चेतावनी बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना से स्पष्ट है कि नई श्रम संहिताएं मजदूरों के अधिकारों को कुचलने वाले काले कानून हैं, जो लाखों लोगों को बर्बादी की ओर धकेल देंगे। वेणुगोपाल ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि एक ही सुबह पूरी श्रमशक्ति को सेवा समाप्ति और पूर्ण एवं अंतिम निपटान पत्र (फुल एंड फाइनल टर्मिनेशन लेटर) थमा दिए गए और गलत तरीके से मुआवजा देकर नौकरी से निकाल दिया गया। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में कर्मचारी की परिभाषा केवल 18,000 रुपये से कम कमाने वालों तक सीमित है, जिससे आईटी कर्मचारियों जैसे अधिकांश लोग इसके दायरे से बाहर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, निश्चित अवधि के अनुबंध को कानूनी मान्यता देकर स्थायी कर्मचारियों को अस्थायी और 'हायर-ऑर-फायर' व्यवस्था में बदलने का रास्ता खोल दिया गया है। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने ये श्रम संहिताएं बड़े कॉरपोरेट घरानों की सुविधा के लिए बनाए हैं और मेहनतकश मजदूरों के अधिकारों को कुचलने के लिए लागू किए हैं। उन्होंने मांग की कि इन कानूनों को संसदीय समीक्षा के लिए वापस भेजा जाए ताकि मजदूरों के पक्ष में संतुलन बहाल किया जा सके।

केजरीवाल ने इथेनॉल-मिश्रित ईंधन को लागू करने के खिलाफ केंद्र सरकार पर साधा निशाना

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार देश पर इथेनॉल-मिश्रित ईंधन को जबरन थोप रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 6 बड़ी ऑटो कंपनियों पर इथेनॉल 20 को सुरक्षित बताने के लिए पत्रकार वार्ता करने का दबाव बनाया गया।आआपा के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोगों के विरोध के बावजूद इथेनॉल 20 पेट्रोल थोप रही है और इसके लिए झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों वाहन मालिकों के विरोध के बावजूद पूरे देश पर जबरदस्ती ई20 पेट्रोल थोपी जा रही है।केजरीवाल ने कहा कि 3 जुलाई को सरकार ने 6 बड़ी ऑटो कंपनियों पर इथेनॉल20 को सुरक्षित बताने के लिए पत्रकार वार्ता करने का दबाव बनाया। तीन कंपनियों ने ऐसा दावा करने से साफ इनकार कर दिया।अरविंद केजरीवाल ने बताया कि मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि पुरानी गाड़ियों में भी ई20 सुरक्षित है और इससे सिर्फ 5–7 प्रतिशत माइलेज घटेगा।उन्होंने कहा कि टोयोटा के आधिकारिक ओनर मैनुअल में केवल इथेनॉल 10 (10 प्रतिशत ई) तक के इस्तेमाल की अनुमति है। मैनुअल में यह भी लिखा है कि ई10 से भी परफॉर्मेंस या माइलेज प्रभावित हो, तो इथेनॉल मुक्त (0 प्रतिशत) पेट्रोल पर वापस लौट जाएं।केजरीवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब कंपनियों के आधिकारिक ओनर मैनुअल कह रहे हैं कि 10 प्रतिशत से ज्यादा इथेनॉल गाड़ियों को तबाह कर देगा, तो सरकार का 20 इथेनॉल को सुरक्षित बताना ग्राहकों के साथ सरासर धोखा है।उन्होंने कहा कि जब कंपनियों के अपने दस्तावेज इथेनॉल 10 की सीमा तय करते हैं, तो पत्रकार वार्ता में इथेनॉल 20 को पूरी तरह सुरक्षित कैसे बताया जा रहा है?केजरीवाल ने सरकारी पत्रकार वार्ता में आई सभी ऑटो कम्पनियों को चिट्ठी लिखने की बात की। उन्होंने सभी कम्पनियों से कहा कि लिखित में वे अपने ग्राहकों को आश्वासन दें की गाड़ी में ई20 इस्तेमाल करने पर यदि माइलेज 10 प्रतिशत से ज़्यादा गिरता है, तो कंपनी उसकी भरपाई करेगी और गाड़ी का कोई भी पार्ट डैमेज होता है, तो कंपनी उसे मुफ़्त में रिप्लेस करेगी।केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने की बात की। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि अगर किसी की गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है, तो उसका हरजाना कौन देगा? साथ ही केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इथेनॉल पर दूसरे देशों का उदाहरण देकर लोगों के विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। जबकि जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में ई10 से ऊपर का फ्यूल इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। जापान तो अभी केवल ई3 ही इस्तेमाल कर रहा है, और थाईलैंड में भी ई10 और ई20 दोनों के विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ब्राजील ही ऐसा देश है जहां ई100 इस्तेमाल हो रहा है, और ब्राजील ने इस ट्रांजिशन के लिए पूरे 50 साल का समय लिया। लेकिन भारत में 2023 में ई20 का ट्रायल किया गया और महज 3 साल में पूरे देश पर ई20 थोप दिया गया।अरविंद केजरीवाल ने सरकार से जनता को ऑप्शन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि फैसला जनता का होना चाहिए कि वे अपनी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डालना चाहते हैं, न कि सरकार का।

सिनेमा, टेलीविज़न, फिल्म, कला, संस्कृती आदि क्षेत्रों में विश्व स्तर पर भारत का नाम रौशन करना हैः संदीप मारवा

लोकतंत्र की शान

नई दिल्लीः अच्छे कर्म करो ईष्वर उसका फल भी अच्छा ही देगा, ईष्वर मेहनत किसी की कभी व्यर्थ नहीं करता बस मेहनत सही दिषा में होनी चाहिए, इस प्रकार के विचार व्यक्त किये मारवा स्टूडियो के निदेषक डा. संदीप मारवा ने, उन्होंने बताया यूपी के नोएडा में 10 मार्च 1991 को मारवा स्टूडियो की स्थापना की। यह दिल्ली एन.सी.आर का प्रथम स्टूडियो था, उस समय से लेकर वर्तमान समय तक मारवा स्टूडियो देष के युवाओं को मनोरंजन और कला के क्षेत्र में विभिन्न स्तर की सेवा, सिनेमा, टेलिविज़न, फैषन, एनिमेषन, अतिथी सत्कार, व्यवसाय, प्रबंधन, फोटोग्राफी, संगीत और अन्य प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। मारवा स्टूडियो ज्ञान, कौषल और तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए एक सक्षम मंच देता है। प्रतिवर्ष हज़ारों विद्यार्थी प्रशिक्षित होकर संगीत कला, एकटिंग आदि क्षेत्र में सफल होकर आगे बढ़ रहे हैं। मारवा स्टूडियो देश के युवाओं के सपनों को सच करने की दिशा में कार्य कर रहा हैं संदीप मारवा एक मात्र ऐसे व्यक्ति जिन्हें 18 मई 2023 को 67 देशों की सरकारों द्वारा भारत के सांस्कृतिक राजदूतों द्वारा नामित किया। उन्होंने 100 से अधिक फिल्म, टेलिविज़न, मीडिया, कला, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों मे कार्य किया है। संदीप मारवा फिल्म जगत के सात विश्व रिकार्ड अपने नाम कर चुके हैं। संदीप मारवा नोएडा फिल्म सिटी, मारवा स्टूडियो और एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एण्ड टेलिविज़न के संस्थापक हैं। संदीप मारवा विश्व स्तर पर लघु फिल्मों के निर्माता हैं 2026 में संदीप मारवा को भारतीय फिल्म महासंघ के एफ.एफ.आई के उपाध्यक्ष के रूप में नामित हुए। अंत में संदीप मारवा ने कहा हमारा प्रयास सिनेमा टेलीविज़न, फिल्म, कला, संस्कृती आदि क्षेत्रों में विश्व स्तर पर भारत का नाम रौशन करना है। हम अपने इस प्रयास में निरंतर कार्यरत हैं। मनुष्य जीवन में सफल होने के लिए बेहतर कार्य करता है।

राष्ट्रीय लोकदल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजीव तोमर का तीस हजारी में भव्य स्वागत

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री त्रिलोक त्यागी जी राष्ट्रीय लोकदल के संगठन राष्ट्रीय महासचिव का दिल्ली बार ऐसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने सम्बोधन में कहा पार्टी के प्रति आपकी निष्ठावान विचारधारा, विश्वास, संघर्षशीलता, ओर समर्पण से राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश में और अधिक सशक्त होगा तथा जनसेवा के हमारे संकल्प को नई ऊर्जा और गति मिलेगी। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब-जब देश को दिशा की जरूरत पड़ी, हमारे देश के अधिवक्ताओं ने सबसे आगे आकर नेतृत्व किया स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य आधार ही हमारे वकील थे।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहभागिता

- प्रबुद्ध कुमार जी, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी, दिल्ली
- रजनीश मलिक जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली
- अमित (आरक्के०), प्रदेश महासचिव- किसान
- मनमोहनसिंह जी, प्रदेश महासचिव, दिल्ली प्रदेश
- अविजित चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष छात्र प्रकोष्ठ
- दयाराम नागर जी, वरिष्ठ नेता एवं समस्त दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारी, सम्मानित अधिवक्ता गण, कार्यकर्ता, गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नई दिल्ली दौरा

6 केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर ऊर्जा, मेट्रो, जल परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि से जुड़े मुद्दों पर की विस्तृत चर्चा

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान सोमवार देर रात और मंगलवार को प्रदेश के हितों की पैरवी और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी समन्वय के लिए 6 केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इन बैठकों में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, शहरी विकास, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल सहित विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की प्रगति को लेकर केन्द्रीय मंत्रियों के साथ विस्तार से चर्चा की। केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम को व्यवस्थित रूप से धरातल पर लागू किया गया है। पहले ही दिन से यहां सभी मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराने के साथ ही हर गांव का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही ग्राम विकास चौपालों की भी सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गांवों में जाकर स्वयं लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली, राज्य में अन्न भंडारण क्षमता के विस्तार एवं आधुनिक वेयरहाउस विकसित करने पर चर्चा की। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के क्षेत्र में राजस्थान की उल्लेखनीय प्रगति को लेकर सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की यह उपलब्धि केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। बैठक के दौरान स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के माध्यम से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को गति प्रदान करने, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के विकास से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। केन्द्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलात मंत्री मनोहर लाल के साथ मुख्यमंत्री ने राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण, आवास एवं शहरी विकास की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की। साथ ही, प्रदेश में ई-बस सेवाओं और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन, यमुना जल परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना सहित प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं एवं भविष्य की कार्ययोजनाओं को लेकर सकारात्मक संवाद किया।

अल्मावेकनिंग फाउंडेशन ने भारतीय पैरा खिलाड़ियों को मोटराइज्ड व्हीलचेयर देकर EXPAND कार्यक्रम को आगे बढ़ाया

लोकतंत्र की शान

गुरुग्रामः भारतीय पैरा खिलाड़ियों के लिए सुगम्यता और समावेशिता को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अल्मावेकनिंग फाउंडेशन ने अपने प्रमुख कार्यक्रम EXPAND के तहत मोटराइज्ड व्हीलचेयर वितरित कीं। यह कार्यक्रम तकनीक और सहायक समाधानों के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन को अधिक सुलभ और आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। इस पहल के तहत भारतीय पैरा खिलाड़ियों को अत्याधुनिक मोटराइज्ड व्हीलचेयर प्रदान की गईं, ताकि उन्हें बेहतर गतिशीलता, आत्मनिर्भरता, सम्मान और खेलों के साथ-साथ दैनिक जीवन में समान भागीदारी का अवसर मिल सके। इस कार्यक्रम का आयोजन गुरुग्राम के सेक्टर-48 स्थित क्लब कैप्री में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) और IGF के सहयोग से किया गया। भारत में पैरा खेलों के बढ़ते विकास के बीच EXPAND कार्यक्रम जैसी पहलें खिलाड़ियों की गतिशीलता से जुड़ी चुनौतियों को कम करने, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी देशवासियों की आस्था पर गंभीर आघात, भाजपा-आरएसएस का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हुआ- कांग्रेस

श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट तत्काल भंग हो, शंकराचार्यों, धर्माचार्यों को शामिल कर नया ट्रस्ट बने- गहलोत

» 'प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें, मंदिर को मिले पूरे चढ़ावे की सूची सार्वजनिक की जाए'

लोकतंत्र की शान

नई दिल्लीः कांग्रेस ने श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी को देशवासियों की आस्था पर गंभीर आघात बताते हुए कहा कि इससे भाजपा-आरएसएस का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की कि मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए। उसकी जगह एक नया ट्रस्ट गठित किया जाए, जिसमें देश के शंकराचार्यों, धर्माचार्यों, साधु-संतों और धार्मिक प्रतिनिधियों को स्थान मिले। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा हो। उन्होंने यह भी मांग की कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक करना पड़ा था, उसी तरह श्रीराम मंदिर को नकदी, सोने-चांदी और अन्य सामान के रूप में मिले पूरे चढ़ावे की सूची को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने इस मामले में चल रही जांच को लीपापोती करार देते हुए कहा कि जब श्रीराम मंदिर से जुड़े हर कार्य का पूरा श्रेय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर लिया था, तो अब इस घोटाले के सामने आने पर वे अपनी जवाबदेही से क्यों बच रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के सामने अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की संरचना शुरुआत से ही त्रुटिपूर्ण रही है। भाजपा-आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने मिलकर एकतरफा तरीके से पूरे मंदिर ट्रस्ट पर अनधिकृत कब्जा कर लिया, लेकिन उसमें किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं की गई। उन्होंने कहा कि संबंधित लोगों को चढ़ावा चोरी होने की जानकारी पहले से थी, लेकिन मामले को दबाए रखा गया।

मर्कज़ी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन ने IIT मंडी के पाठ्यक्रम में पुनर्जन्म और संबंधित विषयों को शामिल किए जाने पर चिंता व्यक्त की

लोकतंत्र की शान

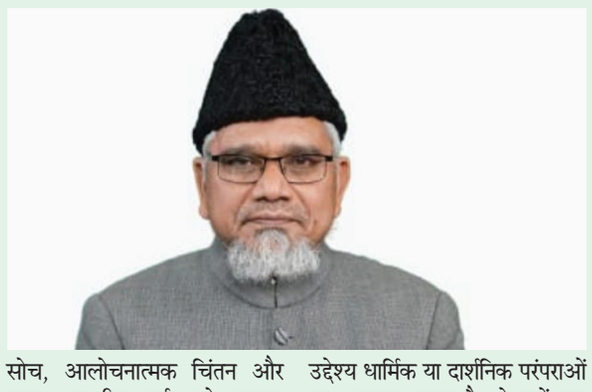

नई दिल्लीः मार्कज़ी तालीमी बोर्ड MTB के चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर रहे प्रो. मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मंडी के अनिवार्य पाठ्यक्रम में पुनर्जन्म, मृत्यु-समीप अनुभव, शरीर से बाहर के अनुभव और सूक्ष्म शरीर जैसे विषयों को शामिल किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि किसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान के अनिवार्य पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को शामिल करने से पहले उनके वैज्ञानिक आधार, शैक्षणिक प्रासंगिकता और संवैधानिक निहितार्थों की समुचित शैक्षणिक कठोरता के साथ जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 छात्रों में वैज्ञानिक सोच, आलोचनात्मक चिंतन और प्रमाण-आधारित तर्क को बढ़ावा देने पर जोर देती है। इस संदर्भ में उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या इन विषयों का मूल्यांकन उन्हीं वैज्ञानिक मानकों के अनुसार किया गया है जो उच्च वैज्ञानिक शिक्षा के संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले अन्य विषयों पर लागू होते हैं। प्रो. सलीम ने आगे कहा कि यदि इन विषयों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य धार्मिक या दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन करना है, तो उन्हें एक अंतर्विषयक फ्रेमवर्क के अंतर्गत और विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन विषय के तहत पढ़ाना अधिक उचित होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह का शैक्षणिक दृष्टिकोण छात्रों को इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और अन्य धार्मिक व बौद्धिक परंपराओं का वस्तुनिष्ठ और संतुलित अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा, जैसा कि दुनिया भर के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में किया जाता है। उन्होंने मीडिया में आई उन खबरों पर स्पष्टीकरण की भी मांग की जिनमें कहा गया है कि भगवद गीता का सामूहिक पाठ सहित कुछ धार्मिक गतिविधियों को अनिवार्य किया गया है। यदि ऐसी रिपोर्टें सही हैं, तो संबंधित संस्थान को आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। प्रो. सलीम ने अंत में इस बात पर जोर दिया कि IIT जैसे राष्ट्रीय संस्थान भारत की वैज्ञानिक और शैक्षणिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण में शैक्षणिक सत्यनिष्ठा, वैज्ञानिक सोच, संवैधानिक मूल्यों और भारत की समृद्ध धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता को लगातार बनाए रखा जाना चाहिए।

संक्षिप्त समाचार

चौधरी मुशीर अली खान के मार्गदर्शन में विकास की रफ्तार तेज, वार्डों में पहुँचे एआईएमआईएम नेता, जनता से किया सीधा संवाद

लोकतंत्र की शान : सैय्यद कुमैल जैदी : संभल। नगर पालिका परिषद सम्भल के विभिन्न वार्डों में एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता मुबश्शिर चौधरी ने सदस्य आसिफ एवं हाफिज वसीम के साथ जनसंपर्क अभियान चलाकर क्षेत्रवासियों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा उनके शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया गया। जनसंपर्क के दौरान मुबश्शिर चौधरी ने कहा कि नगर पालिका परिषद सम्भल की अध्यक्ष आशिया मुशीर अली खान के नेतृत्व में नगर के विकास कार्यों को नई गति मिली है। सड़क, नाली, सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा जनहित से जुड़े अनेक विकास कार्य लगातार कराए जा रहे हैं, जिससे नगरवासियों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पति एवं एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता चौधरी मुशीर अली खान के मार्गदर्शन, दूरदर्शी सोच और जनसेवा के प्रति समर्पण के कारण नगर के विकास को नई दिशा मिली है। जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनना, संबंधित अधिकारियों से उनका समाधान कराना तथा हर वर्ग के लोगों के बीच रहकर उनकी आवाज़ बुलंद करना उनकी कार्यशैली की पहचान बन चुका है। यही कारण है कि नगर के विभिन्न वार्डों में उन्हें जनता का भरपूर स्नेह और विश्वास प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर सदस्य आसिफ एवं हाफिज वसीम ने भी लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और विश्वास दिलाया कि जनहित से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ उठाया जाएगा। जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्रवासियों ने एआईएमआईएम नेताओं का स्वागत करते हुए नगर में कराए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की तथा अध्यक्ष आशिया मुशीर अली खान एवं अध्यक्ष पति चौधरी मुशीर अली खान के नेतृत्व में नगर के निरंतर विकास की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमंगल की कामना के साथ काल भैरव व काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन

वाराणसी। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमंगल की कामना के साथ काशी कोतवाल काल भैरव व बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और विधि विधान से पूजन-अर्चन किया। मुख्यमंत्री ने काल भैरव मंदिर में आरती के साथ विधि विधान से पूजा कर बाबा का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन हाथ जोड़कर स्वीकार किया और बच्चों को दुलारा। इसके पश्चात सीएम ने काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ के दरबार में गर्भगृह में जाकर षोडशोपचार पूजन कर लोक कल्याण की कामना की। यहां बाबा के दर्शन करने आए भक्तों ने मुख्यमंत्री को देखकर 'हर-हर महादेव' का जयकारा लगाया। मुख्यमंत्री वाराणसी में आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु' के बेटे के विवाह समारोह में भी शामिल हुए। उन्होंने इस मांगलिक वेला पर वर-वधू एवं परिजनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।इस मौके पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, खादी ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान, स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, एमएसएमई राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी, महापौर अशोक तिवारी, सदस्य विधान परिषद राय धर्मेंद्र सिंह, विधायक डॉ अवधेश सिंह, सौरभ श्रीवास्तव, त्रिभुवन राम, मंडलायुक्त एस. राजलिंगम, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री के आह्वान पर पुलिस अधिकारियों ने किया पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

लोकतंत्र की शान : सैय्यद कुमैल ज़ैदी , संभल/ सिरसी मुख्यमंत्री के वृक्षारोपण अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकारी संभल एवं थाना हजरतनगर गढ़ी प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में थाना परिसर में पौधरोपण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। क्षेत्राधिकारी संभल ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण को संतुलित नहीं रखते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और स्वस्थ जीवन भी प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक नागरिक को पौधरोपण कर हरियाली बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने कहा कि पौधरोपण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसकी नियमित देखभाल करे, तो पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्राधिकारी संभल एवं थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार की इस पर्यावरण हितैषी पहल की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करने और जनहित के अभियानों में भी बढ़-चढ़कर भागीदारी निभा रही है। अधिकारियों ने सभी नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित रखने की अपील की।

75 जिलों में जेल भरो आंदोलन करने को तैयार किसान

» भीषण गर्मी में भी डटे रहे किसान हजारों किसानों ने लिया हिस्सा

लोकतंत्र की शान, खिज़र अहमद

नजीबाबादः भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं एवं निर्दोष किसानों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को चांदपुरी में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में जनपद बिजनौर सहित आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। पंचायत में किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार और प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की। महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) के

पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसानों के साथ हो रहे अन्याय, फसलों के उचित मूल्य, बिजली आपूर्ति, सिंचाई व्यवस्था तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए यह महापंचायत आयोजित की गई है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुई घटनाओं में कई निर्दोष किसानों को परेशान किया गया है, जिन्हें न्याय दिलाने के लिए संगठन पूरी मजबूती के साथ संघर्ष करेगा। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और निर्दोष लोगों को तत्काल राहत देने की मांग की। महापंचायत में उपस्थित किसानों ने एकजुट होकर किसान हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो संगठन आगे और बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान नेता, पदाधिकारी एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। महापंचायत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई तथा अंत में किसानों की विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रशासन को भेजने का निर्णय लिया गया। महापंचायत में मुख्य रूप से संगठन के पदाधिकारी, क्षेत्रीय किसान नेता तथा हजारों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। किसानों ने एक स्वर में कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

श्रावण मास कांवड़ यात्रा की तैयारियों का एसपी व एएसपी ने किया स्थलीय निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर। आगामी श्रावण मास कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से मंगलवार को पुलिस अधीक्षक रामपुर एवं अपर पुलिस अधीक्षक ने उत्तराखंड सीमा से जुड़े रुद्रविलास, काशीपुर क्षेत्र में कांवड़ मार्ग तथा प्रस्तावित रूट डायवर्जन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षित एवं सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यातायात प्रबंधन, बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती, पार्किंग व्यवस्था तथा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी सहित विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने

तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस प्रशासन ने कहा कि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एसएसपी की जनसुनवाई में फरियादियों की समस्याओं पर त्वरित सुनवाई, समयबद्ध निस्तारण के दिए सख्त निर्देश

लोकतंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) बरेली पुलिस कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना रहा। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, पारिवारिक मामलों, मारपीट, धोखाधड़ी, कब्जे, साइबर अपराध तथा अन्य कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं। एसएसपी ने प्रत्येक प्रार्थना पत्र का बारीकी से परीक्षण करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। एसएसपी ने अधिकारियों से कहा कि जनता की शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक मामले में पीड़ित को न्याय मिले और कार्रवाई पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी या लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ फरियादियों की बात सुनने, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देने तथा

कानून के दायरे में रहकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, शिकायतकर्ताओं को उनके मामलों की प्रगति की जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

नजीबाबाद में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप, पति समेत 6 ससुरालीजनों पर मुकदमा दर्ज

» शादी के ढाई माह बाद उजड़ गया सुहाग

लोकतंत्र की शान, खिज़र अहमद

नजीबाबाद। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम लुकादड़ी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के मायके पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पति समेत छह ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के पूना स्थित शांति नगर निवासी शहनाज खलील शेख ने थाना नजीबाबाद में दी गई तहरीर में बताया कि उनकी पुत्री गुलनाज खलील शेख का विवाह 21 अप्रैल 2026 को ग्राम लुकादड़ी निवासी मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद यामीन के साथ हुआ था। विवाह में अपनी हैसियत के अनुसार जेवर, कपड़े,

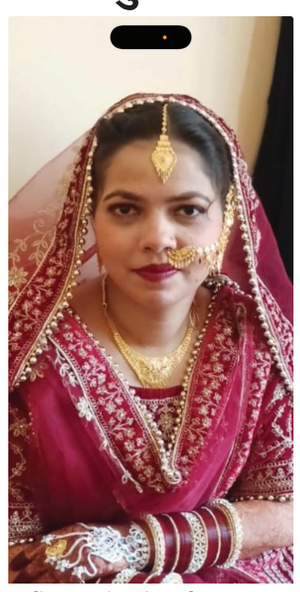

फर्नीचर, बर्तन, बिजली का सामान तथा दो लाख रुपये नकद दिए गए थे। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति मोहम्मद आसिफ, ससुर मोहम्मद यामीन, जेठ मोहम्मद जावेद, ननद शाहना तथा अन्य परिजन शाइस्ता और शबाना कम दहेज का ताना देकर विवाहिता के साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न करते थे। मायके पक्ष का आरोप है कि आरोपी दहेज में कार की मांग कर रहे थे और मांग पूरी न होने पर गुलनाज को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। तहरीर में कहा गया है कि 6 जुलाई 2026 को सभी आरोपियों ने कथित रूप से गुलनाज के साथ मारपीट की और उसे जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। मृतका की मां का कहना है कि जब भी वे बेटी से मिलने जाती थीं, वह अपने साथ हो रहे उत्पीड़न की जानकारी देती थी। घटना के गवाह के रूप में मृतका के पिता खलील शेख का भी उल्लेख किया गया है। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे बोर्ड में गूंजा आंवला का मुद्दा: सांसद नीरज मौर्य ने रखीं 15 बड़ी मांगें, एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव से लेकर नए ओवरब्रिज तक उठाई आवाज

लोकतंत्र की शान

(बरेली/नई दिल्ली | उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) आंवला लोकसभा क्षेत्र के सांसद नीरज मौर्य ने रेलवे बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक में बरेली मंडल और अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े रेल यात्रियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए विकास का व्यापक खाका पेश किया। सांसद ने रेलवे बोर्ड के समक्ष लगभग 15 प्रमुख मांगें रखते हुए स्पष्ट कहा कि यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो बरेली मंडल की रेल व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा और लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। बैठक में सांसद ने सबसे पहले बिशारतगंज, आंवला और रेवती बहोड़ा खेड़ा रेलवे स्टेशनों पर महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों से प्रतिदिन हजारों यात्री सफर करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव न होने के कारण लोगों को अतिरिक्त दूरी तय कर बरेली अथवा अन्य बड़े स्टेशनों तक जाना पड़ता है। इससे समय और धन दोनों की हानि होती है। सांसद नीरज मौर्य ने बरेली-भुज आला हजरत एक्सप्रेस में एसी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अतिरिक्त कोच लगाए जाने की मांग भी प्रमुखता से रखी। उन्होंने रेलवे बोर्ड को बताया कि इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है

और एसी कोचों में लंबी वेटिंग रहती है। अतिरिक्त कोच लगाए जाने से यात्रियों को राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी। रेल सुरक्षा और सुगम यातायात को लेकर सांसद ने भमोरा-आंवला तथा अखा-गैनी रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) निर्माण की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि इन क्रॉसिंगों पर अक्सर लंबा जाम लगता है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ओवरब्रिज बनने से स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों और आपातकालीन सेवाओं को काफी सुविधा मिलेगी।

बिशारतगंज, आंवला और रेवती बहोड़ा खेड़ा में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव, बरेली-भुज आला हजरत एक्सप्रेस में अतिरिक्त एसी कोच, नई रेल सेवाओं और यात्री सुविधाओं के विस्तार को लेकर रेलवे बोर्ड के समक्ष रखा विस्तृत प्रस्ताव।

रामपुर जिला अस्पताल में सीएमएस बीसी सक्सेना ने संभाला है जब से कार्यभार, अस्पताल परिसर में आवारा कुत्तों का आतंक बना चिंता का विषय

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर। उत्तर प्रदेश/ रामपुर के जिला सरकारी अस्पताल में नए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. बी.सी. सक्सेना ने अपना कार्यभार संभाला अस्पताल में लापरवाही दिखाई दे रही है। उनके सामने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने की बड़ी चुनौती है। इस बीच अस्पताल परिसर में आवारा कुत्तों की बढ़ती मौजूदगी मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल परिसर के कई हिस्सों में आवारा कुत्ते खुलेआम घूमते दिखाई देते हैं। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी लोगों ने चिंता

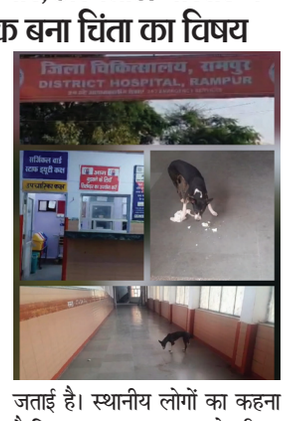

जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन को परिसर में स्वच्छता, सुरक्षा और आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, ताकि मरीजों को सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। नए सीएमएस डॉ. बी.सी. सक्सेना से लोगों को उम्मीद है कि वे अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार करते हुए परिसर को आवारा कुत्तों से मुक्त कराने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

सीएम योगी ने सुल्तानपुर में वितरित किए चेक व प्रशस्ति पत्र

लोकतंत्र की शान

सुल्तानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जनपद को 819 करोड़ रुपये से अधिक की 99 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसी दौरान उन्होंने ग्राम्य विकास, उद्योग, श्रम एवं पशुपालन विभाग सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए। इससे स्वरोजगार, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं चेक, प्रशस्ति पत्र पाकर लाभार्थियों के मंच पर चेहरे खिल उठे।

योजनाओं के लाभार्थी-
श्रीमती अनीता कुमारी – मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत घर की चाबी मिली।

श्रीमती सीमा मौर्या – विद्युत सखी एनआरएलएम थर्मल प्रिंटर का वितरण।

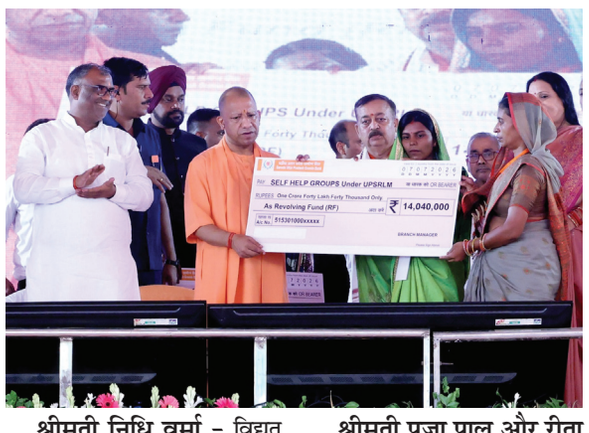

श्रीमती निधि वर्मा – विद्युत सखी एनआरएलएम थर्मल प्रिंटर का वितरण।

श्रीमती संजू साहू – बीसी सखी एनआरएलएम प्रशस्ति पत्र।

श्रीमती साधना देवी और नजमा – सेल्फ हेल्प ग्रुप (यूपीएसआरएलएम) के तहत 409 समूहों का 6 करोड़ 13 लाख 50 हजार का चेक।

श्रीमती पूजा पाल और रीता (समूह प्रतिनिधि) – 1.40 करोड़ रुपये का चेक प्राप्त किया। श्रीमती रीमा देवा और आराधना जायसवाल (संगठन पदाधिकारी) – 55 लाख 50 हजार का चेक प्राप्त किया।

पीएम उद्यमी युवा योजना

अमन मौर्या – 5 लाख का चेक प्राप्त किया।

श्रीमती निर्मला – 3 लाख रुपये का प्राप्त किया।

श्री दया शंकर भार्गव – 5 लाख रुपये का चेक प्राप्त किया।

श्री करण – 5 लाख रुपये का चेक प्राप्त किया।

मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना

श्री लक्ष्मण – 31 हजार रुपये का चेक प्राप्त किया।

श्री अरुण कुमार – 31 हजार रुपये का चेक प्राप्त किया।

श्रीमती लीलावती देवी – 25 हजार रुपये का चेक प्राप्त किया।

श्रीमती पूनम – 25 हजार रुपये का चेक प्राप्त किया।

नंद बाबा दुग्ध योजना

श्रीमती लक्ष्मी जायसवाल – 5.90 लाख रुपये का चेक प्राप्त किया।

श्री गुलाब पति त्रिपाठी – 5.90 लाख रुपये का चेक प्राप्त किया।

रामपुर में गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान मौत, स्वास्थ विभाग मोन सवाल है ऐसे अस्पतालों पर कब होगी सीज और बंद की बड़ी कार्रवाई

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर/ उत्तर प्रदेश/रामपुर मे बीती रात रज़ा डिग्री कॉलेज के निकट हबीब नर्सिंग होम मे महिला की मृत्यु हो गई , डॉक्टर अस्पताल छोड़कर फरार हो गए । परिजनों ने ज़ोरदार प्रदर्शन किया,मोके पर जाकर थाना गंज पुलिस और प्रशासन ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों ने थाना गंज पहुंच कर दी तहरीर। आपको बता दें जनपद रामपुर में फर्जी अस्पतालों की बाढ़ आई हुई है रामपुर cmo और सीएमएस की मिली भगत से फर्जी अस्पताल जनपद में चल रहे हैं किसी भी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं है और ना ही अस्पतालों के मानक पूरे हैं ना डॉक्टर हैं यहां तक की कुछ अस्पतालों में देखा गया है कि स्टाफ से डिलीवरी कराई जाती है अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी मौन है बड़े-बड़े अफसर है खामोश बैठे हैं क्योंकि उनका मोटा पैसा बंधा हुआ है कुछ अस्पताल में तो डॉक्टरों की डिग्रियां भी नहीं है हर गली मोहल्ला चौक चौराहे पर अस्पताल खोल दिए हैं जैसे की परचून की दुकान हो या फिर जनरल स्टोर की तरह हॉस्पिटल

चल रहे हैं, आखिरी एस अस्पतालों पर स्वास्थ विभाग शिकंजा कब कसेगा, अस्पतालों पर कारवाई कब होगी जो किसी की जान से जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं हर रोज जनपद में एक ना एक घटना होती है कहीं गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो जाती है तो कहीं इलाज न मिलने के कारण कहीं दवाइयां गलत लिखने के कारण किसी न किसी की मौत होती है इसके जिम्मेदार आखिर खामोश क्यों हैं, क्या डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के यही दिशा निर्देश डॉक्टर को है कि फर्जी अस्पताल धड़ल्ले से चलवाए जाएं या फिर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के आदेशों की अवहेलना सरकार को बदनाम करने की साजिश डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग लगातार रच रहे हैं ऐसे में देखना होगा कि क्या बड़ी कार्रवाई होती है सभी की निगाहें टिकी हुई है

संक्षिप्त समाचार

वैशाली में 2 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, अभियुक्तों की निशानदेही पर हथियार बरामद

लोकतंत्र की शान :हाजीपुर। वैशाली में बिहार एसटीएफ की विशेष टीम और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई काजीपुर थाना क्षेत्र में की गई, जहां से अपराधियों के पास से देसी कारबाइन और एक देसी कट्टा बरामद किया गया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान राजकपूर और राकेश कुमार के रूप में हुई है। बिहार पुलिस मुख्यालय के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर काजीपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव से हथियार बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त राजकपूर एक शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट सहित कुल 16 मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से पुलिस की तलाश में था। इस मामले में काजीपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

शालिनी कुमारी चांदपुरा की नई थानाध्यक्ष बनीं, बिट्टू कुमार को महुआ थाना भेजा गया

लोकतंत्र की शान :हाजीपुर। वैशाली पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने तीन पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया है। इनमें शालिनी कुमारी को चांदपुरा थाने का अध्यक्ष बनाया गया है। यह नियुक्तियां लोकहित और प्रशासनिक दृष्टिकोण से की गई हैं। जंदाहा थाने की अपर थाना अध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक शालिनी कुमारी को चांदपुरा थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चांदपुरा के वर्तमान थाना अध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक बिट्टू कुमार को महुआ थाना अनुसंधान इकाई में भेजा गया है। वहीं, महुआ थाने के अपर थाना अध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक राजू कुमार पाल को सहदेई का नया थाना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापना स्थल पर योगदान देने और अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है। यह बदलाव हाल ही में सहदेई थाना अध्यक्ष गौतम कुमार साह के निलंबन के बाद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने गौतम कुमार साह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया था। एसपी ने बताया था कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गंभीर घटना हुई थी, जिसमें उसके सिर और पैर में चोटें आई थीं। पीड़ित ने सहदेई थाने में आवेदन दिया था, लेकिन लगभग 20 दिनों तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। पीड़ित ने सीधे पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। मामले की तत्काल समीक्षा और जांच के बाद यह सामने आया कि तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने लापरवाही बरती थी। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाना अध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी।

शादी से कैमरामैन दुल्हन की नाबालिग बहन को लेकर भागा, वैशाली में वीडियोग्राफी के दौरान हुई घटना

लोकतंत्र की शान :हाजीपुर। वैशाली जिले के गोरौल थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह से दुल्हन की नाबालिग बहन को वीडियोग्राफी करने आया कैमरामैन कथित तौर पर लेकर फरार हो गया। इस मामले में लड़की के भाई ने गोरौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, जंदाहा थाना क्षेत्र के चमरूपुर गांव निवासी गोलू कुमार बड़ी बहन की शादी में वीडियोग्राफी के लिए आया था। शादी समारोह के दौरान गोलू ने दुल्हन की 16 वर्षीय छोटी बहन से बातचीत की और उसका मोबाइल नंबर ले लिया था। घटना 3 जुलाई की रात करीब 12 बजे की है। नाबालिग लड़की बाथरूम जाने का बहाना बनाकर घर से निकली, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, पर उसका कहीं पता नहीं चल सका। परिजनों ने कैमरामैन गोलू से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। गोरौल थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अपहृत लड़की की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। लड़की के भाई ने अपने आरोप में बताया कि गोलू कुमार ने शादी के दौरान उसकी छोटी बहन का नंबर ले लिया था और उससे मोबाइल पर बात करने लगा था। उन्होंने यह भी बताया कि 3 जुलाई को गोलू लड़की के घर भी गया था। जब परिजनों ने गोलू से संपर्क किया, तो उसने लड़की के अपने पास होने से इनकार कर दिया। भाई के अनुसार, गोलू अलग-अलग 8 मोबाइल नंबरों से फोन करता था।

मुस्लिम लड़के ने फौजी बनकर हिन्दू लड़की को फंसाया

लोकतंत्र की शान :मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक मुस्लिम युवक ने खुद को सेना का जवान बताकर हिन्दू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी का नाम मो. अरमान है। पीड़िता का कहना है कि अरमान ने शादी का झांसा देकर मुझसे पैसे लिए, जबकि वो पहले से शादीशुदा है। बाद में पता चला कि मो. अरमान सेना का जवान नहीं बल्कि साइकिल की दुकान पर पंचर बनाता था। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने सेना जैसी हेयरकट, कमांडो ड्रेस और वीडियो कॉल पर वर्दी और हथियार दिखाकर युवती का भरोसा जीता। इसके बाद खुद को कभी पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात तो कभी आतंकियों के कब्जे में फंसा बताकर कई किस्तों में रुपए मंगवाता रहा। सकरा थाना क्षेत्र की 21 साल की युवती के आवेदन पर सदर थाना में मुख्य आरोपी मो. अरमान समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जनवरी 2026 में फेसबुक पर मो. अरमान की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने अपनी पहचान को विश्वसनीय बनाने के लिए पूरी तैयारी की थी। युवती से पहली मुलाकात से पहले उसने सेना के जवानों जैसी हेयरकट कराई और कमांडो ड्रेस पहनकर मिलने पहुंचा। आरोपी अलग-अलग बहाने बनाकर युवती से रुपए मंगवाता रहा। कभी वह खुद को पाकिस्तान सीमा पर ड्यूटी पर तैनात बताता, तो कभी आतंकियों के कब्जे में होने की कहानी सुनाकर पैसों की जरूरत बताता था।

आरजेडी झंडे वाली गाड़ी से युवक का अपहरण

लोकतंत्र की शान :मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में थार सवार ने युवक का अपहरण किया। थार पर राजद झंडा लगा है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी मो. रहमान ने खुद को जिला सचिव बताया है। आरोपी रहमान ने पीड़ित युवक आयुष कुमार का अपहरण उसके घर के पास काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से किया था। उसे गाड़ी में बैठाया और करीब 30 किमी तक घुमाया। उसके साथ गाड़ी में मारपीट भी की गई। गाड़ी रहमान के अलावा और भी लोग थे। इस दौरान अपहरण की सूचना पर पुलिस एक्टिव हो गई। गिरफ्तारी के डर से बदमाशों ने आयुष को सड़क किनारे छोड़ दिया। मामला रविवार दोपहर का है। पुलिस ने घटना के 4 घंटे के बाद गिरफ्तारी की है। आज पुलिस ने मामले की जानकारी पीसी कर दी है। पुलिस के अनुसार दोपहर करीब 3:30 बजे काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से एक युवक के अपहरण की सूचना मिली। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिलेभर में घेराबंदी कर सघन वाहन जांच और छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया। सरैया थाना क्षेत्र से अपहरण में इस्तेमाल थार गाड़ी के साथ आरोपी मो. रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर का रहने वाला है। जांच में पुलिस ने पाया कि थार पर RJD के झंडे के साथ जिला सचिव का बोर्ड भी लगा था। नगर-1 के एसडीपीओ सुरेश कुमार ने बताया कि पूछताछ और अनुसंधान में सामने आया है कि अपहृत युवक और गिरफ्तार आरोपी के बीच पहले से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर भी तनाव था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी एक युवती से दोस्ती थी और घायल युवक उसे लगातार धमकी देता था। इसी विवाद के चलते अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित आयुष कुमार के लिखित आवेदन पर काजी मोहम्मदपुर थाना में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।

डॉ. अग्रवाल आई हॉस्पिटल की एक बड़ी उपलब्धि, एक दुर्लभ जन्मजात नेत्र दोष से पीड़ित 51 वर्षीय व्यक्ति की आँखों की रौशनी वापस लौटी

लोकतंत्र की शान : मोहम्मद शबीब आलम

कोलकाता, 7 जुलाई : डॉ. अग्रवाल आई हॉस्पिटल, कोलकाता में जन्मजात 'आइरिस कोलोबोमा' (एक दुर्लभ जन्मजात दोष जिसमें आइरिस का एक हिस्सा पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता) की समस्या से जूझ रहे 51 वर्षीय मरीज़ का सफलतापूर्वक उपचार किया गया। पीड़ित को बचपन से ही बाईं आँख से कम नज़र आता था लेकिन अस्पताल में कई डे-केयर प्रक्रियाओं के बाद उनकी नज़र वापस लौट आई। उनका 'सिंगल-पास फोर-थ्रो (SFT) प्यूपिलोप्लास्टी' नामक उपचार किया गया। यह एक आइरिस रीकंस्ट्रक्शन तकनीक है जिसे डॉ. अग्रवाल आई हॉस्पिटल के चेयरमैन प्रो. अमर अग्रवाल ने विकसित किया है। इस प्रक्रिया में असामान्य पुतली की मरम्मत की जाती है जिससे दृष्टि व दृश्य गुणवत्ता दोनों में सुधार आता है। उपचार के बाद, रोगी की बाईं आंख की रौशनी 40% से बढ़कर 75% हो गई है। रोगी ने कई वर्षों के दौरान बड़े-बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों को दिखाया लेकिन हर जगह से यहीं खबर आई कि उनका केस बहुत पेचीदा है और आँखों की रौशनी वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं है। जन्मजात आइरिस कोलोबोमा के अलावा, रोगी की आँखों के अगले और पिछले हिस्सों में भी कुछ असामान्यताएँ थीं, जिससे लेंस और रेटिना पर असर पड़ता था। उन्हें फैकोडोनेसिस (कमजोर सपोर्ट के कारण लेंस में असामान्य कंपन) और ज़ोनुलोपैथी (लेंस को अपनी जगह पर टिकाए रखने वाले फाइन फाइबर्स –ज़ोन्यूल्स की कमजोरी) की समस्या थी। इन समस्याओं के कारण एम्ब्लियोपिया (लेज़ी आई) हो गया, जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें दृष्टि ठीक से विकसित नहीं हो पाती क्योंकि बचपन से ही मस्तिष्क को प्रभावित आँख से कोई स्पष्ट छवि नहीं मिल पाती है। चालीस साल का होने के बाद, रोगी की दोनों

आँखों में मोतियाबिंद भी हो गया, जिससे उनकी दृष्टि और भी बिगड़ गई। जन्मजात आइरिस कोलोबोमा, ज़ोन्यूलर कमज़ोरी, प्रभावित रेटिना और एम्ब्लोपिया जैसी कई स्थितियों के कारण सर्जरी करना बहुत मुश्किल था। ज़ोन्यूलर सपोर्ट की कमी के कारण मोतियाबिंद हटाने के बाद इंट्राऑकुलर लेंस (IOL) लगाना भी तकनीकी रूप से कठिन था, क्योंकि स्थिर सपोर्ट न होने पर 'अफ़ैकिया' (एक ऐसी स्थिति जिसमें आँख में कोई प्राकृतिक या कृत्रिम लेंस नहीं रह जाती) का जोखिम था। इससे सर्जरी और भी जटिल हो गई। इसके अलावा, कोलकाता के बहुत कम सर्जनों के पास SFT पपिलोप्लास्टी प्रक्रिया करने की प्रशिक्षा थी। नतीजतन, कोई भी अस्पताल उनका केस लेने को तैयार नहीं था। हालांकि, स्पेशलिस्ट नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. समर सेनगुप्ता की अगुवाई में एक सर्जिकल टीम ने रोगी की बाईं आँख की कार्यात्मक दृष्टि सफलतापूर्वक बहाल करके यह कारनामा कर दिखाया। टीम ने मानक फैकोइमल्सीफिकेशन का उपयोग करके मोतियाबिंद की सर्जरी भी की। चूंकि कमज़ोर ज़ोन्यूल्स की वजह से कैप्सुलर बैग अस्थिर था, इसलिए एक कैप्सुलर टेंशन रिंग (एक लचीला उपकरण जो कैप्सुलर बैग को स्थिर करता है और सुरक्षित इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन के लिए आवश्यक सपोर्ट प्रदान करता है) लगाई गई। टिप्पणी करते हुए डॉ. सेनगुप्ता ने कहा, "रोगी सबसे पहले अपनी दाईं आँख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए हमारे पास आए थे। यह ऑपरेशन सफल रहा, जिसके बाद अपनी बाईं आँख के पेचीदे मामले का उपचार करवाने की हिम्मत बंधी। हर जगह से उन्हें यहीं सुनने को मिलता कि सर्जरी या तो मुमकिन नहीं है या सर्जरी करवाने के बाद भी उनकी दृष्टि बहाल होने की संभावना कम है। इसलिए, वे बरसों से यही मानते रहे थे कि उनकी बाईं आँख की रोशनी कभी लौट नहीं पाएगी। सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने के बाद, हमने उनकी आँख की कई समस्याओं को ठीक करने के लिए एक खास सर्जरी प्लान बनाया। आज, उनकी बाईं आँख की रौशनी वापस लौट आई है, वे अपने रोज़मर्रा के काम बिना किसी की मदद के कर पा रहे हैं और सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे मुश्किल मामलों के बाद रोगियों की दृष्टि और आत्मविश्वास वापस लौटते देखना पूरी टीम के लिए बहुत संतोषजनक अनुभव है।" हालिया सफलताओं की एक और कहानी है, एक 45 वर्षीय गृहिणी की, जिन्हें दोनों आँखों में हाई मायोपिया (−10.00 डायोप्टर से अधिक) और इलोंगेटेड एक्सियल लेंथ की समस्या थी, जिसके कारण उन्हें दूर की चीज़ें बहुत धुंधली दिखाई देती थीं। वे दशकों से मोटे चश्मे पहनती थीं, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगा पाती थीं और रोज़मर्रा की गतिविधियाँ करने में दिक्कतें आती थीं। पारंपरिक लेज़र विज़न करेक्शन (LASIK) करना संभव न था क्योंकि उनकी कॉर्निया इतनी पतली थी कि इतनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव पॉवर वाली लेज़र ट्रीटमेंट करना सुरक्षित नहीं था।

सहरसा पुलिस को बड़ी सफलता, 30 मोबाइल व सोने का सिक्का बरामद; चोरी के तीन आरोपी गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान : मो. ज़ियाउद्दीन

सहरसाः सदर थाना पुलिस ने चोरी की वारदातों का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 30 चोरी के मोबाइल फोन, एक सोने का सिक्का, एक सोने की मांगटीका तथा एक नथिया बरामद की है। पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में चोरी की घटनाओं पर बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार 17 मई 2026 को नया बाजार तथा 20 मई 2026 को न्यू कॉलोनी वार्ड संख्या-39 में अज्ञात चोरों द्वारा मोबाइल फोन एवं सोने के आभूषणों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में सदर थाना में कांड दर्ज कर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था। विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान एवं छापेमारी के दौरान 30 मोबाइल फोन, एक सोने की मांगटीका, एक नथिया एवं एक सोने का सिक्का बरामद करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विवेकी कुमार (पिता- विवेक पासवान), विवेकी कुमार (पिता- इंद्रजीत पासवान), दोनों निवासी सराही पासवान टोला, वार्ड संख्या-11 तथा अवनीश कुमार (पिता- घनश्याम मलिक), निवासी सराही मोड़, थाना सदर, जिला सहरसा के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस अन्य चोरी गए सामानों की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सहरसा पुलिस ने कहा कि जिले में चोरी एवं अन्य आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सौरबाजार थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देसी कट्टा व 10 जिंदा कारतूस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान : मो. ज़ियाउद्दीन

सहरसाः जिले में अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सौरबाजार थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस तथा एक टेम्पो के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंगलवार की रात सौरबाजार थाना पुलिस द्वारा वाहन जांच एवं गश्ती के दौरान डिग्गा चौक के समीप एक संदिग्ध टेम्पो को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस वाहन को देखकर चालक टेम्पो घुमाकर भागने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर ग्राम राजवंशी के पास दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपनी पहचान सुनील कुमार (पिता- धर्मेंद्र साह, निवासी- गोलमा बाजार टोला, वार्ड संख्या-18, थाना पतरघट) एवं संजय यादव (पिता- गणेश यादव, निवासी- गाजीपीता, वार्ड संख्या-14, थाना सोनवर्षाराज), दोनों जिला सहरसा के रूप में बताई। वाहन एवं आरोपियों की तलाशी लेने पर संजय यादव के पास रखे एक गमछे से एक देसी कट्टा एवं 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बरामद हथियार के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुलिस ने हथियार एवं कारतूस को जब्त करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में सौरबाजार थाना कांड संख्या-177/2026 के तहत आर्म्स एक्ट की धाराओं 25(1-बी)ए, 26 एवं 35 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूछताछ में संजय यादव ने बताया कि उसके बड़े साले शंकर यादव अपनी मां से चल रही जमीन संबंधी विवाद के कारण उक्त हथियार लेकर जमीन पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है तथा अन्य संभावित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सहरसा पुलिस ने कहा कि जिले में अवैध हथियार रखने वालों एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिले के 31 चिन्हित स्थलों पर सफलतापूर्वक आयोजित हुआ सहयोग शिविर, डीएम व एसपी ने किया निरीक्षण

लोकतंत्र की शान : मो. ज़ियाउद्दीन

सहरसाः पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को सहरसा जिले के विभिन्न प्रखंडों में चिन्हित 31 स्थलों पर सहयोग शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस क्रम में जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिहाग ने कहरा प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन, सिरादेयपट्टी में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने लाभुकों को नियमानुसार निष्पादित आवेदनों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रमाण-पत्र वितरित किए। साथ ही शिविर में उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार ने कहा कि सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन से प्राप्त आवेदनों का त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से प्राप्त लगभग शत-प्रतिशत आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेष लंबित मामलों का भी शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध हो सके। जिले में आयोजित सभी 31 सहयोग शिविरों का संचालन वरीय पदाधिकारियों एवं वरीय उप समाहर्ताओं के पर्यवेक्षण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिला प्रशासन ने आमजन को अधिक से अधिक संख्या में ऐसे शिविरों का लाभ उठाने और अपनी समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्राप्त करने की अपील की है।

हाथीदह पुलिस ने 100 किलो गांजा जब्त किया, 6 तस्कर दबोचे गए

लोकतंत्र की शान : पटना

पटना जिले के हाथीदह थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तीन चार पहिया वाहनों से 100 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया और मौके से पांच अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई।

लग्जरी गाड़ियों में गांजे की बड़ी खेप ले जा रहे थेः जानकारी के अनुसार, हाथीदह थाना प्रभारी अभिषेक कुमार को सूचना मिली थी कि तस्करों का एक गिरोह लग्जरी गाड़ियों में गांजे की बड़ी खेप ले जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष ने तुरंत एक विशेष टीम गठित की और चिन्हित स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी।

जांच के दौरान, पुलिस टीम ने संदिग्ध परिस्थितियों में आ रहे तीनों चार पहिया वाहनों को रुकने का इशारा किया। वाहन चालकों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल की मुस्तैदी से उन्हें घेरकर रोक लिया गया। वाहनों की गहन तलाशी लेने पर उनके अंदर बने गुप्त तहखानों और सीटों के नीचे छिपाकर रखा गया 100 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

पुलिस ने गांजे की खेप और तीनों वाहनों को जब्त कर पांचों तस्करों को हिरासत में ले लिया। इस सफलता के बाद स्थानीय पुलिस ने तुरंत अपने वरीय अधिकारियों को सूचित किया।

पटना जू में अगले सप्ताह से देख सकेंगे व्हाइट टाइगर

लोकतंत्र की शान : पटना

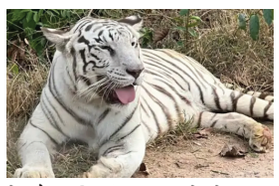

पटना जू में अगले सप्ताह से लोग व्हाइट टाइगर का दीदार कर सकते हैं। दिल्ली जू से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आए व्हाइट टाइगर को डिस्प्ले किया जाएगा। इसके अलावा 6 संघाई हिरण, 4 वाइट ब्लैकबक, 4 रोजी पेलिकन, 4 पेंटेड स्टॉर्क, 2 ग्रीन इगुआना और 2 सिल्वर फिजेंट भी लाए गए हैं। दिल्ली जू से आए संघाई हिरणों में दो नर और चार मादा हैं, जबकि वाइट ब्लैकबक में दो नर और दो मादा हैं। इसके अलावा 25 जुलाई तक कर्नाटक के शिवमोगा जू से दो नर गौर लाए जाएंगे। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

अभी पटना जू में सिर्फ़ 2 मादा गौर हैं। 2 नर गौर लाने से पटना जू में गौर की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। शिवमोगा जू को देश की पहली विशेष 'गौर सफारी' के रूप में विकसित की गई है। इसके तहत मैसूरू चिड़ियाघर से लाए गए भारतीय गौर रखे जाते हैं।

इगुआना के लिए बन रहा एक कांच का बाड़ाः वहीं, रोहतक जू से दो ग्रीन इगुआना और दो सिल्वर फिजेंट लाए गए हैं। वाइट ब्लैकबक और ग्रीन इगुआना भी दर्शकों के लिए आकर्षण साबित होंगे। खासकर ग्रीन इगुआना को पहली बार पटना जू में देखा जा सकेगा।

हर जिले में निगरानी थाना-ओपी खोलने की तैयारी

लोकतंत्र की शान : पटना

बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अपनी पहुंच और कार्रवाई को और मजबूत करने की तैयारी में है। हर जिले में एक निगरानी थाना या ओपी खोलने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द विभाग को भेजा जाएगा। इसके अलावा सभी प्रमंडलों में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की भी योजना बनाई गई है। वर्तमान में पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में निगरानी मामलों के लिए विशेष कोर्ट कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते मामलों को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता है। वहीं, अगर अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्व एवं भूमि विभाग के ऑफिसर्स पर हुई है। ये जानकारी ब्यूरो के महानिदेशक (डीजी) जितेंद्र सिंह गंगवार ने सोमवार को पटना में एक पीसी में कही है।

हर डेढ़ दिन में भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज हो रहाः बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई में तेजी आई है। 2025 में अब तक 30 आरोपियों को सजा दिलाई जा चुकी है, जो पिछले 25 वर्षों के औसत से 5 से 6 गुना अधिक है। ब्यूरो अब हर डेढ़ दिन में भ्रष्टाचार का एक नया मामला दर्ज कर रहा है। ब्यूरो के महानिदेशक (डीजी) जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि 2000 से 2024 के दौरान औसतन हर साल 5.6 आरोपियों को सजा दिलाई जाती थी। इस साल अब तक 10 और आरोपियों को सजा मिल चुकी है, यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है।

डीजी गंगवार ने बताया कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज होने की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 2000 से 2024 के बीच सालाना औसतन 72 एफआईआर दर्ज होती थी, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 122 हो गई, जो लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

ट्रैप केस की संख्या भी बढ़ीः मौजूदा वर्ष में एफआईआर दर्ज होने की रफ्तार पिछले वर्ष से भी अधिक है। पहले जहां औसतन दो दिन में एक एफआईआर दर्ज होती थी, वहीं अब यह औसत घटकर 1.4 दिन हो गया है, यानी लगभग हर डेढ़ दिन में एक नया मामला दर्ज हो रहा है। इसके अतिरिक्त, ट्रैप कार्रवाई में भी दोगुनी से अधिक तेजी आई है। पिछले 25 वर्षों में सालाना औसतन 49 ट्रैप केस होते थे, जबकि वर्ष 2025 में इनकी संख्या 101 तक पहुंच गई है। डीजी ने उम्मीद जताई कि वर्तमान वर्ष में यह आंकड़ा तीन गुना तक पहुंच सकता है। भ्रष्ट अफसरों की 102 करोड़ की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई डीजी ने बताया कि भ्रष्टाचार के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले लोक सेवकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जारी है।

संक्षिप्त समाचार

पलवल : टैंकर से एलपीजी गैस चोरी, चालक के खिलाफ केस दर्ज

लोकतंत्र की शान : पलवल। सदर थाना क्षेत्र के बहरौला गांव स्थित एक ढाबे पर खड़े एलपीजी गैस से भरे टैंकर से करीब 3400 किलो गैस चोरी होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि टैंकर चालक गैस की हेराफेरी कर फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर मालिक की शिकायत पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। सदर थाना प्रभारी हरी किशन ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के रोहिणी निवासी अजय गोयल ने शिकायत दी है कि उनका टैंकर गुजरात के पोरबंदर से एलपीजी गैस लेकर रुड़की (उत्तराखंड) जा रहा था। टैंकर को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोह पिंगरी, फराह निवासी विष्णु चला रहा था। शिकायत के अनुसार, चालक दो जून से टैंकर को बहरौला स्थित पंडित जी के ढाबे पर खड़ा कर गया था। इसके बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया। संदेह होने पर टैंकर की जांच कराई गई तो उसमें गैस की भारी कमी मिली। जांच अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर ढाबा संचालक से पूछताछ की और टैंकर का वजन कराया। वजन 20,650 किलोग्राम पाया गया। जांच में सामने आया कि चालक ने कथित रूप से मालिक को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की नीयत से टैंकर में भरी एलपीजी में से करीब 3400 किलोग्राम गैस निकाल ली। पुलिस ने आरोपी चालक से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद मिला। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

फरीदाबाद : मेट्रो स्टेशन के बाहर आईबी अधिकारी से मोबाइल झपटा

लोकतंत्र की शान : फरीदाबाद। शहर में मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला सराय मेट्रो स्टेशन का है, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने गृह मंत्रालय में कार्यरत एक अधिकारी के हाथ से मोबाइल फोन झपट लिया और फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, बिहार के गया जिले के रहने वाले संजीत कुमार वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में कार्यरत हैं। वह सरकारी कार्य से दिल्ली आए हुए थे। 5 जुलाई की रात वह फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी स्थित अपने दोस्त के घर जाने के लिए सराय मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े होकर कैब बुक कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे और पलक झपकते ही उनके हाथ से मोबाइल फोन झपटकर बदरपुर की ओर फरार हो गए। संजीत कुमार ने बताया कि घटना इतनी तेजी से हुई कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। उन्होंने बताया कि मेट्रो स्टेशन के बाहर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने के कारण बदमाशों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया। घटना के बाद उन्होंने आसपास काफी तलाश की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को घटना की जानकारी दी और सराय ख्वाजा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सराय ख्वाजा थाना प्रभारी राकेश ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस घटनास्थल और आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

एसआई भर्ती-2021 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी हो सकते हैं पुनः परीक्षा में सम्मिलित

लोकतंत्र की शान : अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 20 सितंबर 2026 को होने वाली एसआई भर्ती पुनः परीक्षा में वर्ष 2021 की मूल भर्ती में आनलाइन आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अस्थाई रूप से शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। इसके तहत पुनः परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण अपडेट करने के लिए 8 से 22 जुलाई 2026 तक का समय दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने 8 मई 2026 को जारी प्रेस नोट के तहत पहले ही अपने आवेदन अपडेट कर लिए हैं, उन्हें दोबारा संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। संशोधन के बाद स्क्रीन पर आ रहे स्वघोषणा पत्र को स्वीकार कर ओटीपी से सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना एवं दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।संशोधन करने से पहले अभ्यर्थियों को अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसके तहत लाइव फोटो, अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आइडी से लॉगिन कर माई रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर आवेदन में सुधार कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी का ओटीआर पुरानी आईडी से अन्य आइडी पर माइग्रेट हो चुका है, तो वे फैच एप्लीकेशन फॉर्म विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र नई एसएसओ आईडी या ओटीआर में ट्रांसफर करने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है, तो वे आयोग के कैंडिडेट ग्रीवेंस पोर्टल पर जाकर 15 जुलाई 2026 तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भर्ती की पात्रता शर्तें 3 फरवरी 2021 एवं शुद्धि-पत्र 7 जून 2021 को जारी मूल विज्ञापन के अनुसार और परीक्षा पाठ्यक्रम पूर्व में 22 मई 2026 को जारी प्रेस नोट के अनुसार ही रहेगा। अभ्यर्थी केवल अपने मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, पत्राचार का पता, लाइव फोटो, अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर में ही सुधार कर सकेंगे। इसके अलावा आयु, शैक्षणिक योग्यता और आरक्षण जैसी मूल प्रविष्टियां पहले की तरह ही यथावत रहेंगी।आयोग सचिव ने बताया कि यह अवसर राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा 2 जुलाई 2026 के पारित किए गए अंतरिम आदेश के क्रम में दिया जा रहा है। इसके तहत एसआई भर्ती -2021 के तहत पूर्व भर्ती परीक्षा- 2021 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अनन्तिम रूप से सम्मिलित किया जा रहा है। पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में ओटीआर में प्रयुक्त फोटो, हस्ताक्षर तथा अंगूठा निशानी के प्रयोग करने के लिए सहमति प्रदान करते हुए फाइनल सब्मिट कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना अनिवार्य होगा, जो अभ्यर्थी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे, उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बीस हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान :टोंक/जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टोंक इकाई ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के उंचा पटवार हल्का में कार्यरत पटवारी भंवर सिंह को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपित ने न्यायालय के निर्णय की पालना में परिवादी के पिता के पक्ष में जमीन की डिक्री दर्ज (दाखिल) करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी।एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी की हेल्पलाइन 1064 पर शिकायत मिली थी कि आरोपित पटवारी भंवर सिंह न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए परिवादी के पिता के पक्ष में जमीन की डिक्री दर्ज करने के बदले 20 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है तथा राशि नहीं देने पर परिवादी को परेशान कर रहा है।शिकायत के सत्यापन के दौरान 25 जून 2026 को आरोपित ने 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की और राशि लेने पर सहमति जताई। शिकायत का सत्यापन सही पाए जाने पर एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई। उप महानिरीक्षक पुलिस नारायण टोगस (अजमेर रेंज) के सुपरवीजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रैप अधिकारी ऋषिकेश मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। ट्रैप के दौरान आरोपित पटवारी ने परिवादी को अपनी कार में बैठाया और रिश्वत की राशि कार के डैशबोर्ड बॉक्स में रखवाई। एसीबी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बॉक्स से 20 हजार रुपए बरामद कर आरोपित को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया।

एसपी सीधी ने जनसुनवाई में सुनी फरियादियों की समस्याएं

» सभी प्रभारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निर्देशन में आज दिनांक 7 जुलाई 2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी में साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपनी शिकायतें एवं समस्याएं प्रस्तुत कीं। पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता एवं संवेदनशीलता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में भूमि एवं संपत्ति विवाद, महिला संबंधी अपराध, साइबर अपराध, मारपीट, धोखाधड़ी, राजीनामा एवं अन्य कानून व्यवस्था से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन की तथ्यपरक जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए तथा शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जनसुनवाई में प्राप्त आपसी पारिवारिक विवादों के मामलों को सौहार्दपूर्ण एवं विधिक समाधान की दिशा में आवश्यक परामर्श प्रदान करते हुए पैरा लीगल वालेंटियर के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अग्रेषित किया गया, जिससे संबंधित पक्षों को विधिक सहायता एवं काउंसलिंग उपलब्ध कराई जा सके। महिला अपराध, वरिष्ठ नागरिकों एवं समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित शिकायतों की प्राथमिकता से सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पूर्व से लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर संबंधित थाना प्रभारियों एवं विवेचना अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग, शिकायतकर्ताओं से सतत संवाद एवं निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने कहा कि जनसुनवाई आमजन और पुलिस के बीच विश्वास का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निराकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही जिन मामलों का समाधान आपसी सहमति एवं विधिक परामर्श से संभव है, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रभावी ढंग से निराकृत कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। जनसुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी, उप पुलिस अधीक्षक अजाक सुजीत कड़वे, लोकल थाना प्रभारी सहित पैरा लीगल वालेंटियर उपस्थित रहे। जिले के अन्य राजपत्रित अधिकारी एवं थाना/चौकी प्रभारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े।

थाना परिसर में घुसकर प्रधान आरक्षक पर जानलेवा हमला

सिर में आई गंभीर चोट, जिला चिकित्सालय में भर्ती

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के भुईमाड़ थाना परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने थाना परिसर में घुसकर ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक पर हमला कर दिया। हमले में प्रधान आरक्षक बलबीर निखरे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार भुईमाड़ निवासी ओमप्रकाश द्विवेदी (21 वर्ष), पिता वैजनाथ द्विवेदी दोपहर थाना परिसर पहुंचा और किसी बात को लेकर विवाद करने लगा। विवाद बढ़ने पर उसने अपने पास रखें डंडे से प्रधान आरक्षक बलबीर निखरे के सिर पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से प्रधान आरक्षक गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गए। घटना के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों ने घायल प्रधान आरक्षक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी पहुंचाया। चिकित्सकों ने उनके सिर में गंभीर चोट होने पर 23 टांके लगाए। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय सीधी रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 351, 115, 132, 121 एवं 196 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है तथा घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। इस घटना ने थाना परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हमले के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।

कलेक्टर श्री तिवारी ने आदतन अपराधी को 5 माह तक पुलिस थाना में उपस्थित होने के दिए निर्देश

लोकतंत्र कि हसन रसीद जिला जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी गतः कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष तिवारी ने ग्राम टेढ़ी थाना माधवनगर निवासी फूलमति उर्फ फूला लुनिया पति राकेश लुनिया उम्र 48 वर्ष के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आगामी 5 माह की अवधि तक प्रतिमाह की 15 तारीख को पुलिस थाना माधवनगर में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री तिवारी ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। फूलमती एक आदतन अपराधी है और वर्ष 2016 से ही माधवनगर थाना क्षेत्र में लगातार अपराध करते चली आ रही है। इसके विरूद्ध अब तक कुल 7 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें आमजन के साथ गाली-गलौज करना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध शराब का विक्रय करना तथा अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर बलवा जैसे अपराध शामिल है। पुलिस द्वारा फूलमती के विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। परंतु, आदतन अपराधी के आचरण-व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। फूलमती उर्फ फूला लुनिया द्वारा आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी के प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए आगामी 5 माह तक पुलिस थाना माधवनगर में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

मंडी पहुंची कांग्रेस, किसानों की पीड़ा सुनी -25% मूंग खरीदी, डीएपी-यूरिया की कमी और पेट्रोल-डीजल संकट पर उठाई आवाज़

लोकतंत्र कि शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी। किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष एड. अमित शुक्ला ने कृषि उपज मंडी का दौरा कर किसानों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना। किसानों ने बताया कि शासन द्वारा मात्र 25 प्रतिशत मूंग की खरीदी किए जाने से बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने से वंचित हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के बीच धान की रोपाई का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन सबसे अधिक आवश्यक डीएपी खाद किसानों को उपलब्ध नहीं हो रही है। इसके स्थान पर अन्य प्रकार की खाद दी जा रही है, जबकि फसल की आवश्यकता के अनुरूप डीएपी और यूरिया दोनों की पर्याप्त उपलब्धता बेहद जरूरी है। खाद की कमी के कारण किसान समय पर खेती का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही कई क्षेत्रों में पेट्रोल-डीजल की कमी से भी कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष एड. अमित शुक्ला ने कहा कि सरकार किसानों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। जब किसान खेती के सबसे महत्वपूर्ण समय से गुजर रहे हैं, तब उन्हें डीएपी, यूरिया और पेट्रोल-डीजल जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है। सरकार तत्काल पर्याप्त मात्रा में डीएपी एवं यूरिया उपलब्ध कराए, मूंग खरीदी का प्रतिशत बढ़ाए तथा पेट्रोल-डीजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करे, ताकि किसानों को राहत मिल सके।

OBC महासभा का हुंकार, 20 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास घेराव, आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन

» कटनी से उठी आवाज, प्रदेशभर से जुटेंगे हजारों कार्यकर्ता, लंबित मांगों पर सरकार को चेतावनी, अधिकार और न्याय की लड़ाई तेज

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समाज के अधिकारों, प्रतिनिधित्व और लंबित मांगों को लेकर अब संघर्ष निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ओबीसी महासभा कटनी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में संगठन ने 20 जुलाई 2026 को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के घेराव का ऐलान करते हुए प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा की। संगठन का कहना है कि यदि वर्षों से लंबित मांगों पर अब भी गंभीर पहल नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष ने बताया कि भोपाल में होने वाले इस प्रदर्शन में मध्यप्रदेश के सभी जिलों से ओबीसी महासभा के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल होंगे। आंदोलन का उद्देश्य सरकार का ध्यान उन महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकर्षित करना है, जिनका सीधा संबंध सामाजिक न्याय, समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है।<महासभा ने प्रमुख मांगों में जातिगत जनगणना शीघ्र कराए जाने, ओबीसी आरक्षण से जुड़े 13 प्रतिशत होल्ड को समाप्त करने तथा प्रदेश में सामाजिक और जनसरोकार से जुड़े मामलों में प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग दोहराई। संगठन का कहना है कि इन विषयों पर लगातार मांग उठाने के बावजूद अपेक्षित समाधान नहीं मिला, जिससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण आंदोलन जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। इसलिए प्रदेशभर के ओबीसी समाज से अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की गई है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से यह आंदोलन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है और क्या लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल सामने आती है। यदि संवाद और समाधान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, तो यह आंदोलन प्रदेश की राजनीति और सामाजिक विमर्श का बड़ा विषय बन सकता है।

350 से अधिक फरियादियों की उम्मीद बने कलेक्टर विकास मिश्रा, जनसुनवाई में दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर जोर, अधिकारियों को संवेदनशीलता से कार्य करने के निर्देश

(ऋचा पाण्डेय, ब्यूरो प्रमुख)लोकतंत्र की शान

सीधी। जिला पंचायत सभागार में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 350 से अधिक आवेदकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सभी प्रकरणों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आमजन को वास्तविक राहत दिलाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को बिना अनावश्यक विलंब के लाभ मिले और किसी भी आवेदक को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जिन मामलों का मौके पर समाधान संभव था, उनमें तत्काल कार्रवाई कराई गई, जबकि शेष प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच कर निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी गोपद बनास प्रिया पाठक, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने आवेदकों से चर्चा कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की और नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

गुरुग्रामः शेयर में ठगी के लिए खाता बेचने का आरोपी मुंबई से गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

गुरुग्राम। थाना साइबर दक्षिण गुरुग्राम पुलिस ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध करवाने वाले एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। छह अगस्त 2025 को थाना साइबर दक्षिण में एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करवाने के नाम पर उससे 33 लाख 55 हजार रुपए की ठगी की गई है। शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।प्रबंधक थाना साइबर अपराध दक्षिण की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में चेतन सूर्यकांत जगताप निवासी उल्हासनगर, जिला ठाणे महाराष्ट्र को छह जुलाई 2026 को मुंबई से प्रोडक्शन पर लेकर गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता से ठगी गई राशि में से 25 लाख 70 हजार रुपए सीधे आरोपी चेतन जगताप के नाम के बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे।पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यह बैंक खाता चार प्रतिशत कमीशन पर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था, जिसका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया गया। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। मामला अनुसंधानाधीन है और नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।

कोष्टा में मिले मानव कंकाल पर गरमाई चुरहट की सियासत

» मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक, ली जानकारी

» पुलिस के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन आज

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

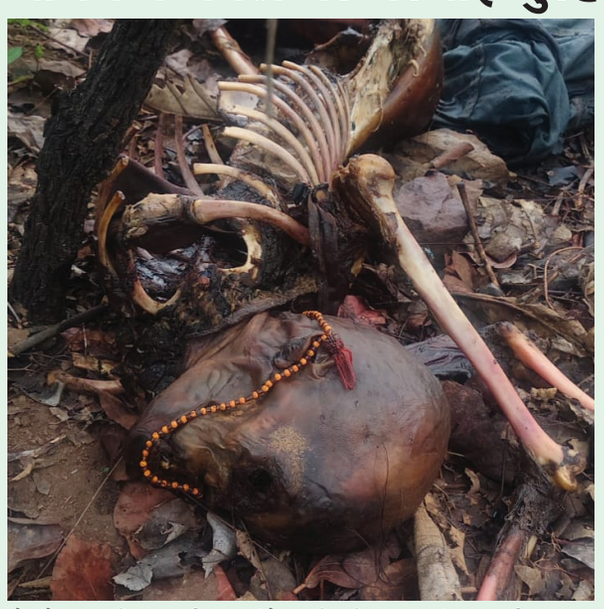

सीधी। चुरहट थाना क्षेत्र के ग्राम कोष्टा में 30 जून को मिले मानव कंकाल के मामले ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। उधर इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस द्वारा थाने का घेराव किए जाने की चेतावनी दी है। घटना को लेकर परिजनों का दावा है कि कंकाल चुरहट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टीकट खुर्द मवई निवासी राजराखन साकेत की लापता पुत्री का है। मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस पर समय से एफआईआर दर्ज नहीं करने और लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी स्वयं घटनास्थल पहुंचे और जांच की प्रगति का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि फिलहाल कंकाल की पहचान केवल भौतिक साक्ष्यों के आधार पर की गई है, जो अंतिम और निर्णायक नहीं मानी जा सकती। एसपी ने बताया कि कंकाल का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद डीएनए मिलान के आधार पर ही मृतक की पहचान की पुष्टि होगी और उसी के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई मामलों में प्रारंभिक भौतिक पहचान बाद में गलत साबित हुई है, इसलिए वैज्ञानिक जांच का इंतजार करना आवश्यक है। एफआईआर दर्ज करने में देरी के आरोपों पर एसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करती है। उन्होंने बताया कि गुमशुदगी या अपराध का मामला पीड़िता की अंतिम लोकेशन के आधार पर दर्ज किया जाता है। कंकाल मिलने के बाद संबंधित प्रकरण दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में है और जांच की हर प्रगति से उन्हें अवगत कराया जा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

नेपाल-कंबोडिया मानव तस्करी और साइबर अपराध के खिलाफ बढ़ाएंगे सहयोग

काठमांडू। नेपाल और कंबोडिया मानव तस्करी, साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी (स्कैम) अभियानों के खिलाफ आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। कंबोडिया के फ्नोम पेन्ह में एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक के दौरान नेपाल के राजदूत धन बहादुर ओली ने कंबोडिया के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय की स्थायी राज्य सचिव ईट सोफिया से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमा पार संगठित अपराध से निपटने, खुफिया व सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने और संस्थागत क्षमता के निर्माण के लिए संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। नेपाली दूतावास के अनुसार राजदूत ओली ने कंबोडिया में चल रहे ऑनलाइन स्कैम सेंटरों से नेपाली नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहयोग के लिए कंबोडिया की शाही सरकार को धन्यवाद दिया। बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर भी चर्चा की गई। हाल ही में नेपाल ने कंबोडियाई भागीदारों के सहयोग से नेपाल नेत्र ज्योति संघ और लुम्बिनी आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर (राणा-अंबिका आई हॉस्पिटल) के संयुक्त प्रयासों से कंबोडिया के कम्पोंग चाम प्रांत में एक मुफ्त आंख उपचार शिविर का आयोजन किया था। कंबोडिया ने इस पहल की सराहना की, जबकि नेपाल ने कंबोडियाई नागरिकों की बढ़ती मांग को देखते हुए आंखों की देखभाल में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने और एक और उन्नत नेत्र उपचार शिविर आयोजित करने की इच्छा जताई। दोनों पक्षों ने उपयुक्त द्विपक्षीय समझौतों और संस्थागत तंत्रों के माध्यम से व्यापार और निवेश को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा की। वे शिक्षा, कृषि और पर्यटन में सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर सहमत हुए। दोनों देशों के बीच पर्यटन की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए दोनों पक्षों ने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी और कंबोडिया के प्रसिद्ध सांस्कृतिक व धार्मिक विरासत स्थल 'अंगकोर वाट' के बीच संपर्क को मजबूत करके बौद्ध और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों ने मौजूदा सहयोग की समीक्षा करने और साझेदारी के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नेपाल और कंबोडिया के विदेश मंत्रालयों के बीच जल्द से जल्द 'द्विपक्षीय परामर्श तंत्र' की बैठक बुलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

नेपाल में सत्तारूढ़ दल के संशोधित विधान में बड़ा बदलाव, प्रधानमंत्री बालेन्द्र पर शिकंजा कसा

काठमांडू। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) ने अपने संशोधित पार्टी विधान में महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा है। नए नियम के अनुसार यदि संसदीय दल का नेता यानी प्रधानमंत्री पार्टी अध्यक्ष के नीतिगत निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसे पद से हटाया जा सकेगा। संशोधित विधान में पार्टी अध्यक्ष के काम, कर्तव्य और अधिकारों के तहत 'संसदीय दल के साथ समन्वय' को वैचारिक और राजनीतिक नेतृत्व का हिस्सा बनाया गया है। इसके तहत अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह स्वयं संसदीय दल का नेता नहीं है, तो भी वह संसद में पार्टी की आधिकारिक नीति, सिद्धांत, निर्णय और दृष्टिकोण के प्रभावी प्रतिनिधित्व तथा क्रियान्वयन के लिए संसदीय दल को आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन दे सकेगा। विधान में स्पष्ट उल्लेख है कि पार्टी अध्यक्ष द्वारा दिए गए ऐसे नीतिगत निर्देशों का पालन करना संसदीय दल, उसके नेता यानि प्रधानमंत्री और सभी सांसदों का अनिवार्य दायित्व होगा। इस प्रावधान के अनुसार, यदि पार्टी अध्यक्ष के निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो संबंधित संसदीय दल के नेता को पद से हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। यह व्यवस्था विधान की धारा 68 (1) में शामिल की गई है। धारा में कहा गया है कि यदि संसदीय दल का नेता धारा 11(क) (3) के तहत पार्टी अध्यक्ष द्वारा दिए गए नीतिगत मार्गदर्शन का पालन नहीं करता है, तो उसे पदमुक्त किया जा सकता है। इसी धारा में अध्यक्ष को संसदीय दल को नीतिगत दिशा-निर्देश देने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। इस नए प्रावधान के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने द्वारा जारी नीतिगत निर्देशों का पालन संसदीय दल के नेता और सभी आरएसपी सांसदों के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई नेता या सांसद इन निर्देशों की अनदेखी करता है, तो अध्यक्ष को उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए संसदीय दल के नेता को पद से हटाने का अधिकार प्राप्त होगा।

खराब मौसम के मद्देनजर एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित मुंबई और कई इलाकों में भारी बारिश के कारण हालात खराब हो चुके हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में तो सरकार की तरफ से भी लोगों को सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं, नई दिल्ली में भारी बारिश को देखते हुए टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर सहित कई इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने 'एक्स' पर जारी एक पोस्ट में कहा कि खराब मौसम की वजह से दिल्ली आने-जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ सकता है। यात्रा में कोई परेशानी न हो, इसके लिए हम यात्रियों को सलाह देते हैं कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले इस लिंक पर जाकर फ़्लाइट का ताज़ा स्टेटस देख लें: https://airindia.com/in/en/manage/flight-status.html आपकी समझदारी और सहयोग के लिए धन्यवाद। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही नई दिल्ली सहित उसके आसपास के इलाकों के लिए आने वाले पांच दिनों में भारी बारिश और आंधी का अनुमान जताया गया है। आज भी कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। इस बारिश से भले गर्मी से लोगों को राहत मिली लेकिन भारी बारिश की चेतावनी ने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के कई जिलों के लिए सात, आठ और नौ जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

देश ने कारगिल के 'शेरशाह' कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके बलिदान दिवस पर किया याद, शीर्ष नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। कारगिल युद्ध के महानायक, परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर मंगलवार को पूरे देश ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित केंद्र सरकार के कई मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य राजनीतिक नेताओं ने कारगिल के 'शेरशाह' के नाम से विख्यात इस वीर सपूत के अदम्य साहस, अद्वितीय नेतृत्व, राष्ट्रभक्ति और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने कहा कि कैप्टन विक्रम बत्रा का जीवन और उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रसेवा, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति का अमिट आदर्श है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने संदेश में कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान दुर्गम पर्वतीय चोटियों पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने असाधारण साहस, निडर नेतृत्व और अटूट राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा सदैव देशवासियों को राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देती रहेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दुर्गम चोटियों पर विजय प्राप्त कर दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा का अदम्य साहस, अटूट संकल्प और अप्रतिम पराक्रम उन्हें 'शेरशाह' के रूप में अमर बनाता है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के प्रति उनका सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता रहेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कैप्टन विक्रम बत्रा की शौर्यगाथा युगों-युगों तक देश की भावी पीढ़ियों को मातृभूमि की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देती रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर वीरता की ऐसी अमिट मिसाल स्थापित की, जो प्रत्येक भारतीय को 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ देशसेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी।

वायनाड में सुरंग परियोजना में भूस्खलन, 3 मजदूरों की मौत

एजेंसी, वायनाड

केरल के वायनाड जिले के कल्लाडी क्षेत्र में निर्माणाधीन ट्विन-टनल परियोजना स्थल पर मंगलवार को हुए भीषण भूस्खलन में कम-से-कम तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों को आशंका है कि कई मजदूर अब भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। घटना के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), अग्निशमन एवं बचाव सेवा, पुलिस तथा जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों ने युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया है। राहत दल ने अबतक 9 घायल मजदूरों को सुरक्षित निकाल कर अस्पताल पहुंचाया है। घायलों की पहचान हिरन कुमार, दिलीप, सूरज यादव, संजय टापुर, रजनीश, तन्मय घोष, कुडम्मल, संतोष और कुंजू के रूप में हुई है। सभी का उपचार बीम्स अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है।

अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण परियोजना स्थल के समीप मिट्टी और चट्टानों का बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। हादसे के समय सुरंग निर्माण परियोजना में कंक्रीट का कार्य चल रहा था। इसी दौरान रिटेनिंग वॉल तथा खुदाई की गई मिट्टी का हिस्सा धंस गया, जिसके बाद पहाड़ी ढलान से भारी मात्रा में मिट्टी, चट्टान और कीचड़ तेजी से नीचे आ गया। देखते-ही-देखते निर्माण स्थल का एक बड़ा हिस्सा मलबे में दब गया और वहां कार्यरत मजदूरों को संभलने का अवसर तक नहीं मिला। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (डीईओसी) के अनुसार, राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। हालांकि भारी मात्रा में जमा मलबा, लगातार हो रही बारिश और फिसलन भरे हालात बचाव कार्य में बड़ी चुनौती बने हुए हैं। प्रशासन यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि मलबे के नीचे कितने मजदूर और कर्मचारी फंसे हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, निर्माण स्थल के समीप स्थित मजदूरों के अस्थायी शिविर और कुछ वाहन भी भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। प्रशासन ने बताया कि पिछले 24 घंटों में क्षेत्र में लगभग 265 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी पूरी तरह जलसंतृप्त (वॉटर सैचुरेटेड) होकर अस्थिर हो गई। एहतियात के तौर पर रविवार से निर्माण कार्य रोक दिया गया था लेकिन परियोजना स्थल पर मौजूद कई मजदूर और अन्य कर्मचारी हादसे की चपेट में आ गए।

कई अन्य के दबे होने की आशंका

वायनाड के भूस्खनल पर प्रियंका व वेणुगोपाल ने जताई चिंता

एजेंसी, नई दिल्ली

नई दिल्ली। केरल के वायनाड जिले के कल्लाडी इलाके में मंगलवार को भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में दो लोगों की मौत पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने चिंता व्यक्त करते हुए राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन को पूरा सहयोग देने की अपील की है।

कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि वायनाड के कल्लाडी में भारी वर्षा से हुआ भूस्खलन बेहद चिंताजनक है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में पूरी तरह जुटा हुआ है तथा एनडीआरएफ की टीमें भी जल्द तैनात की जाएंगी। उन्होंने सभी यूडीएफ कार्यकर्ताओं से राहत प्रयासों में प्रशासन को पूरा सहयोग देने की अपील की और पीड़ितों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर कहा कि भूस्खलन में फंसे लोगों को निकालने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन स्वयं राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं, वहीं, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी पहुंच चुके हैं। जिला प्रशासन, मंत्री टी सिद्दिकी और एपी अनिल कुमार, स्थानीय कार्यकर्ताओं और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। उन्होंने यूडीएफ कार्यकर्ता और आमजनों से प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए राहत और बचाव कार्यों में सहयोग करने की अपील की।

उल्लेखनीय है कि केरल के वायनाड जिले के कल्लाडी क्षेत्र में निर्माणाधीन ट्विन-टनल परियोजना स्थल पर मंगलवार को हुए भीषण भूस्खलन में कम-से-कम तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों को आशंका है कि कई मजदूर अब भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। घटना के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), अग्निशमन एवं बचाव सेवा, पुलिस तथा जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं।

चढ़ावा चोरी के पुख्ता सबूत दें राजनीतिक दल वरना चुनावी स्टंटबाजी से बचें

एजेंसी, लखनऊ

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने अयोध्या के राममंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो भी राजनीतिक दल इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनसे ट्रस्ट को पुख्ता सबूत मांगने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आरोपों के समर्थन में साक्ष्य नहीं दिए जाते हैं तो इसे केवल राजनीतिक स्टंट माना जाएगा। इसी मुद्दे से यह पार्टियां चुनाव में उतरना चाहती हैं।

बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि, अयोध्या में श्रीराम मन्दिर के बाद अब उत्तराखण्ड में भी बद्रीनाथधाम चढ़ावा में चोरी व गबन आदि होने का मामला सुर्ख़ियों में हैं। इन दोनों विख्यात धार्मिक स्थलों में इनके ट्रस्ट से जुड़े मुख्य प्रबन्धकों की सही से जांच होनी चाहिये।क्योंकि ऐसी आम चर्चा है कि निचले स्तर पर जो भी गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए या तो मुख्य प्रबन्धकों की मिलीभगत है या फिर उनकी लापरवाही की वजह से यह सबकुछ हुआ है। अतः इस प्रकरण की अब सही से जांच जरूरी है। इस मामले में सरकार व एसआईटी को भी विशेष ध्यान देना है।

उन्होंने कहा कि राजनैतिक दल सपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी आदि के जो वरिष्ठ नेता श्रीराम मन्दिर चढ़ावे में काफी मोटी रकम की चोरी व ग़बन आदि होने की बात कह रहे हैं, उनसे भी इसके पुख़्ता सबूत लेने चाहिये, ताकि कोई भी चोरी व गबनकर्ता बच ना सके वरना इसकी आड़ में इसे कोरी राजनीति ही माना जायेगा।

मप्र के मैहर में चलते ट्रक में पीछे से घुसी तेज रफ्तार एक्सयूवी कार, पांच युवकों की मौत

एजेंसी, मैहर

मध्य प्रदेश के मैहर जिले में सोमवार देररात नेशनल हाइवे-30 पर हुए सड़क हादसे में पांच युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा नादन देहात थाना क्षेत्र के रिगरा गांव के पास देररात करीब 2 बजे हुआ। तेज रफ्तार महिंद्रा एक्सयूवी-700 आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर में एसयूवी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी छह युवक वाहन के अंदर फंस गए।

सूचना मिलते ही डायल-112, हाइवे पेट्रोलिंग और नादन देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी युवकों को वाहन से बाहर निकाला गया। इनमें पांच की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि गंभीर रूप से घायल एक युवक को अमरपाटन सिविल अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए सतना रेफर किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी युवक अमरपाटन जनपद उपाध्यक्ष मनोज पटेल का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। हादसे ने कुछ ही पलों में जश्न की खुशियों को मातम में बदल दिया।

पुलिस ने मृतकों की पहचान अंकुर पटेल (40) पुत्र गोविंद पटेल, मृदुल पटेल (32) पुत्र महेंद्र पटेल, विजय पटेल (30) पुत्र नागेंद्र पटेल, हरीशंकर पटेल (25) पुत्र नागेंद्र पटेल और शिवा पटेल (23) पुत्र संजू पटेल के रूप में की है। चार युवक मैहर जिले के तनाजा के रहने वाले थे, जबकि शिवा पटेल नरोरा गांव के थे। हादसे में ओम पटेल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जान गंवाने वाले सभी युवक पूर्व विधायक स्वर्गीय लालजी भाई पटेल और पूर्व कांग्रेस विधायक स्वर्गीय मथुरा पटेल के परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं। अंकुर पटेल खेती के साथ व्यवसाय करते थे। मृदुल पटेल वेयरहाउस का संचालन करते थे। विजय पटेल जबलपुर में नौकरी करते थे। हरीशंकर पटेल खेती करते थे। संजीव पटेल नौकरी करते थे। ट्रक चालक चितरंजन दास चंदेल के अनुसार, ट्रक लगभग 40-45 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। अचानक पीछे से तेज गति से आ रही एक्सयूवी ट्रक में आकर भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के पीछे के दोनों टायर क्षतिग्रस्त हो गए, हालांकि वाहन पलटने से बच गया।प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और सामने चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी नहीं बनाए जाने को दुर्घटना का संभावित कारण माना जा रहा है। हादसे के बाद हाइवे पर कुछ देर यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कराया गया। नादन देहात थाना प्रभारी पंचराज सिंह ने बताया कि हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है।

नासिक में बादल फटने का खतरा टला, गुजरात के लिए चेतावनी जारी

एजेंसी, मुंबई

नासिक में बादल फटने का संभावित खतरा अब टल गया है, क्योंकि भारी बारिश का मुख्य केंद्र गुजरात के सूरत की ओर बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसके चलते गुजरात के कई जिलों में 'रेड अलर्ट' जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। विभाग ने मंगलवार को कहा कि बादल अहिल्यानगर होते हुए गुजरात के सूरत की ओर सरक रहे हैं। इससे नासिक जिले पर फिलहाल बादल फटने का खतरा फिलहाल टल गया है, लेकिन जिले में तेज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मुंबई , ठाणे, पालघर , पुणे, रायगढ़ , सातारा और रत्नागिरी में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है।

भारतीय मौसम विभाग के अधिकारी अनुपम कश्यपी ने बताया कि नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर इलाके छाए करीब 450 एमएम के बादल धीरे -धीरे अहिल्यानगर होते हुए गुजरात की ओर सरक रहे हैं। साथ ही मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में बुधवार तक भारी बारिश की संभावना है। विदर्भ के कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश की भी संभावना है।

इस चेतावनी को देखते हुए नासिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आयुष प्रसाद ने प्रशासन को चुस्त और सतर्क रहने का आदेश दिया है। आयुष प्रसाद ने नागरिकों को मौसम में बदलाव को देखते हुए बिना वजह अपने घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों को नासिक और त्र्यंबकेश्वर इलाकों में घूमने के लिए झरनों, नदियों या घाटों पर जाने से पूरी तरह बचना चाहिए।

इस बीच, आज सुबह 7 बजे से नासिक के त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ इलाकों में बारिश जारी है, वहीं नासिक में गोदावरी नदी भी दो धाराओं में बह रही है। । नासिक में पूरी रात हो रही बारिश की वजह से गोदावरी नदी के जलस्तर में वृद्धि हुी है। रामकुंड और गांधी झील जलमग्न है। सुबह धार्मिक रस्मों के लिए आने वाले टूरिस्ट अपनी जान जोखिम में डालकर यहां पूजा-पाठ करते दिखे। । प्रशासन की अपील के बावजूद टूरिस्ट अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।

मौसम विज्ञान विभाग की घोषणा के अनुसार, नासिक जिले में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और संभावित हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, कलवन ने 7, 8 और 9 जुलाई 2026 के दौरान श्री सप्तश्रृंगगढ़ धार्मिक स्थल, झरनों, ट्रेकिंग पॉइंट्स, नदी के किनारों और टूरिस्ट जगहों पर एंट्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

कांग्रेस ने कोरोहेल्थ में 900 कर्मचारियों की छंटनी पर लेबर कोड को बताया मजदूर विरोधी

एजेंसी, नई दिल्ली

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अमेरिका की हेल्थकेयर एनालिटिक्स कंपनी कोरोहेल्थ द्वारा केरल के कोच्चि और कोझिकोड स्थित ब्रांच में करीब 900 मेडिकल कर्मचारियों की अचानक छंटनी को मजदूर वर्ग के लिए चेतावनी बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना से स्पष्ट है कि नई श्रम संहिताएं मजदूरों के अधिकारों को कुचलने वाले काले कानून हैं, जो लाखों लोगों को बर्बादी की ओर धकेल देंगे।

वेणुगोपाल ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि एक ही सुबह पूरी श्रमशक्ति को सेवा समाप्ति और पूर्ण एवं अंतिम निपटान पत्र (फुल एंड फाइनल टर्मिनेशन लेटर) थमा दिए गए और गलत तरीके से मुआवजा देकर नौकरी से निकाल दिया गया। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में कर्मचारी की परिभाषा केवल 18,000 रुपये से कम कमाने वालों तक सीमित है, जिससे आईटी कर्मचारियों जैसे अधिकांश लोग इसके दायरे से बाहर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, निश्चित अवधि के अनुबंध को कानूनी मान्यता देकर स्थायी कर्मचारियों को अस्थायी और 'हायर-ऑर-फायर' व्यवस्था में बदलने का रास्ता खोल दिया गया है।

कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने ये श्रम संहिताएं बड़े कॉरपोरेट घरानों की सुविधा के लिए बनाए हैं और मेहनतकश मजदूरों के अधिकारों को कुचलने के लिए लागू किए हैं।

मानव तस्करी-अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क मामले में एनआईए की छापेमारी

एजेंसी, पटना

मानव तस्करी और अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में छापेमारी की। फेनहरा थाना क्षेत्र के कालूपाकड़ गांव स्थित आरोपित मोहम्मद कलामुद्दीन के घर पर एनआईए की टीम ने करीब पांच घंटे तक तलाशी अभियान चलाया और उससे विस्तृत पूछताछ की। जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह एनआईए की टीम सुरक्षा बलों के साथ कालूपाकड़ गांव पहुंची और घर को घेरकर तलाशी शुरू की। इस दौरान परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की गई तथा कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की जांच की गई।

जांच एजेंसी के अनुसार, मोहम्मद कलामुद्दीन पर युवकों को विदेश में आकर्षक नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया भेजने वाले नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह गोपालगंज के एक युवक के संपर्क में आया था और उसके माध्यम से लोगों को विदेश भेजने की प्रक्रिया में सहयोग करता था। आरोप है कि वह कंबोडिया जाने वाले युवकों के टिकट और यात्रा संबंधी व्यवस्थाएं कराने में भी मदद करता था। एनआईए की जांच में यह भी सामने आया है कि कंबोडिया पहुंचने के बाद कई भारतीय युवकों को कथित तौर पर उनकी इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाकर रखा जाता था।

चढ़ावा मामले में राम मंदिर ट्रस्ट भंग किया जाए सुप्रीम कोर्ट के जज करें पूरे मामले की जांचः कांग्रेस

एजेंसी, नई दिल्ली

कांग्रेस ने कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अत्यंत गंभीर होने के कारण ट्रस्ट को तत्काल भंग करके नये ट्रस्ट का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि नये ट्रस्ट में संतों और धर्माचार्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब गांव-गांव तक पहुंच चुका है। राम मंदिर से देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन इस मामले ने लोगों की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है। मंदिर ट्रस्ट का गठन एकतरफा तरीके से किया गया और उसमें जवाबदेही की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं रखी गई।

उन्होंने कहा कि यदि यह केवल लापरवाही का मामला था तो फिर प्राथमिकी दर्ज करने, विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने और गिरफ्तारियां करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ट्रस्ट की बैठकों में चोरी को लापरवाही बताया गया, जबकि घटनाक्रम इससे कहीं अधिक गंभीर सवाल खड़े करता है। गहलोत ने आरोप लगाया कि संबंधित लोगों को चोरी की जानकारी पहले से थी, लेकिन मामले को दबाने की कोशिश की गई।

ट्रस्ट और केंद्र सरकार को इस मामले पर पारदर्शी जवाब देना चाहिए, क्योंकि अब तक केवल लीपापोती की जा रही है। जब राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़े कार्यक्रमों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लिया था, तो अब विवाद सामने आने पर उन्हें भी जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। मंदिर परियोजना के शुरुआती दौर में भूमि खरीद से जुड़े विवाद भी सामने आए थे, जहां दो करोड़ रुपये की जमीन 18 करोड़ रुपये में खरीदे जाने के आरोप लगे थे। राम मंदिर के संचालन के लिए धार्मिक संतों और धर्माचार्यों को शामिल कर नया ट्रस्ट गठित किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ने और देश के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की।

बदलता मानसून,बढ़ता संकट, आपदाएँ और जलवायु परिवर्तन :क्या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है? -समग्र व्यापक विश्लेषण

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

- देश के अनेक हिस्सों में अत्यधिक वर्षा, बाढ़, शहरी जलभराव और दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में वर्षा की कमी क़ा संकेत -मौसम का पारंपरिक चक्र तेजी से बदल रहा है
- जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष केवल सरकारों का नहीं प्रत्येक नागरिक का दायित्व - वृक्षारोपण,प्लास्टिक के उपयोग में कमी,पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली जैसे छोटे-छोटे कदम सामूहिक रूप से बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर 21वीं सदी में किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी सैन्य क्षमता,आर्थिक विकास दर अथवातकनीकी उपलब्धियों से नहीं आँकी जाएगी,बल्कि इस बात से भी निर्धारित होगी कि वह जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती के सामने अपने नागरिकों,संसाधनों और विकास की निरंतरता को कितनी प्रभावी ढंग से सुरक्षित रख पाता है।प्राकृतिक आपदाएँ अब अपवाद नहीं रहीं; वे जलवायु परिवर्तन के कारण एक नई वैश्विक वास्तविकता बनती जा रही हैं। इसलिए भारत के लिए यह समय केवल परिस्थितियों का सामना करने का नहीं, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर ऐसी राष्ट्रीय रणनीति विकसित करने का है, जो आने वाली पीढ़ियों को अधिक सुरक्षित,सक्षम और पर्यावरण-अनुकूल भारत प्रदान कर सके।इसलिए मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी,गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूं कि यह समय की माँग है कि जलवायु परिवर्तन को केवल राज्य व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का विषय न मानकर राष्ट्रीय नीति और विकास रणनीति के केंद्र में रखा जाए।सरकार को चाहिए कि आपदा प्रबंधन को केवल राहत और पुनर्वास तक सीमित न रखकर उसे राष्ट्रीय विकास नीति का अनिवार्य अंग बनाया जाए।प्रत्येक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अवसंरचना परियोजना चाहे वह राजमार्ग हो,रेलवे,स्मार्ट सिटी, औद्योगिक गलियारा, बंदरगाह या आवासीय परियोजना उसका जलवायु जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य किया जाना चाहिए। यदि विकास परियोजनाएँ संभावित प्राकृतिक जोखिमों को ध्यान में रखकर बनाई जाएँगी, तो भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान और जनहानि को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।यह दृष्टिकोण अल्पकालिक खर्च अवश्य बढ़ाएगा,परंतु दीर्घकाल में राष्ट्र को कहीं अधिक सुरक्षित और आर्थिक रूप से सटीकता से सक्षम बनाएगा। साथियों,वर्तमान मानसून 7 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक ने देश के अनेक राज्यों को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र केरल,कर्नाटक,उत्तराखंड,हिमाचल प्रदेश,असम तथा पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा, जलभराव, भूस्खलन और नदी तंत्र के उफान ने जनजीवन को प्रभावित किया है। विशेष रूप से महानगरों में कुछ घंटों की वर्षा भी यातायात,स्वास्थ्य सेवाओं,बिजली आपूर्ति और आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर देती है।वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि अनियोजित निर्माण, वनों की कटाई और बदलते वर्षा पैटर्न ने जोखिम को कई गुना बढ़ा दिया है। यह केवल मौसम का उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि विकास और पर्यावरण के बीच असंतुलन का परिणाम भी है।जहाँ पहले कई दिनों तक सामान्य वर्षा होती थी, वहीं अब कुछ ही घंटों में अत्यधिक वर्षा होने लगी है। इससे शहरी जलनिकासी व्यवस्था,नदी तंत्र और पहाड़ी ढलानों पर अचानक दबाव बढ़ता है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों में फ्लैश फ्लड,बादल फटना, समुद्री तूफान और भीषण गर्मी जैसी घटनाएँ पहले की तुलना में अधिक तीव्र और अधिक बार दिखाई दे रही हैं। भारत भी इस वैश्विक परिवर्तन से अछूता नहीं है। साथियों,जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव समाज के उस वर्ग पर पड़ता है जिसकी आजीविका सीधे प्रकृति पर निर्भर है। भारत की बड़ी आबादी कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। असमय वर्षा, लंबे सूखे, ओलावृष्टि और बाढ़ किसानों की मेहनत को कुछ ही घंटों में नष्ट कर देते हैं। इससे खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आय,रोजगार और महँगाई सभी प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में उद्योग,परिवहन पर्यटन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ भी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होकर आर्थिक नुकसान को बढ़ाती हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक

विकास, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न बन चुका है। साथियों, स्थानीय प्रशासन की भूमिका इस परिवर्तन में अत्यंत महत्वपूर्ण है।जिला प्रशासन, नगर निकाय, ग्राम पंचायतें और स्थानीय समुदाय आपदा प्रबंधन की पहली पंक्ति होते हैं। इसलिए प्रत्येक जिले के लिए स्थानीय भूगोल, वर्षा पैटर्न, नदी तंत्र,भूस्खलन संभावित क्षेत्रों तथा शहरी जलभराव के आधार पर स्थानीय आपदा कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिएडिजिटल मानचित्रण रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और मोबाइल आधारित चेतावनी प्रणाली को गाँव-गाँव तक पहुँचाना अब विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता है। जिस प्रकार टीकाकरण या स्वच्छता अभियान जनआंदोलन बने, उसी प्रकार आपदा जागरूकता और जलवायु अनुकूलन को भी जनभागीदारी का अभियान बनाना होगा।शिक्षा इस परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम हो सकती है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार तथा सामुदायिक सेवा जैसे विषयों को व्यवहारिक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। यदि बचपन से ही नागरिकों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और आपदा के समय सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी, तो भविष्य का समाज अधिक जिम्मेदार और अधिक सुरक्षित होगा। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सबसे बड़ी लड़ाई केवल सरकारी नीतियाँ नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक ही जीत सकते हैं। साथियो, हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष केवल सरकारों का नहीं,बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।जल संरक्षण,ऊर्जा की बचत, वृक्षारोपण, प्लास्टिक के उपयोग में कमी, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता, स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण तथा पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली जैसे छोटे-छोटे कदम सामूहिक रूप से बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। प्रकृति के साथ संतुलित संबंध ही मानव सभ्यता की स्थायी सुरक्षा का सबसे प्रभावी मार्ग है।आज भारत एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर तीव्र आर्थिक विकास,आधुनिक तकनीक और वैश्विक नेतृत्व की संभावनाएँ हैं, तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियाँ भी हैं। यदि भारत इन चुनौतियों को दूरदृष्टि, वैज्ञानिक सोच, पारदर्शी शासन, जनभागीदारी और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ अवसर में बदल देता है, तो वह आने वाले दशकों में केवल एक विकसित राष्ट्र ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे सशक्त आपदा-प्रतिरोधी और जलवायु-सुरक्षित लोकतंत्र बनने की दिशा में भी सटिका से अग्रसर होगा। साथियों, इस चुनौती का समाधान केवल सरकारों के पास नहीं है। निजी क्षेत्र और उद्योग जगत की जिम्मेदारी भी कम नहीं है।उद्योगों को पर्यावरणीय मानकों का कठोर पालन, हरित ऊर्जा का उपयोग,कार्बन उत्सर्जन में कमी, जल संरक्षण और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से स्थानीय आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना के निर्माण में योगदान देना चाहिए,उद्योगों को हरित प्रौद्योगिकी अपनानी होगी, शहरों को प्राकृतिक जलनिकासी मार्गों का संरक्षण करना होगा, किसानों को जलवायु -अनुकूल कृषि पद्धतियाँ अपनानी होंगी और प्रत्येक नागरिक को जल संरक्षण,वृक्षारोपण, ऊर्जा बचत तथा पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना होगा। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सबसे प्रभावी लड़ाई जनभागीदारी से ही जीती जा सकती है।आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर विकसित भारत का लक्ष्य है, तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती। यदि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, वैज्ञानिक सोच को नीति का आधार बनाया जाता है और आपदा प्रबंधन को आपदा-प्रतिरोधी विकास में परिवर्तित किया जाता है, तो भारत न केवल अपने नागरिकों को सुरक्षित भविष्य दे सकेगा, बल्कि विश्व के लिए एक अनुकरणीय मॉडल भी प्रस्तुत करेगा। साथियों, भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति भी की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन संस्थाएँ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, अंतरिक्ष आधारित मौसम निगरानी प्रणाली तथा समय पर चेतावनी देने वाली तकनीकों ने अनेक अवसरों पर जनहानि को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चक्रवातों के दौरान समय रहते लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना भारत की प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण है। किंतु बदलती जलवायु परिस्थितियाँ यह संकेत देती हैं कि भविष्य की चुनौतियाँ वर्तमान व्यवस्थाओं से कहीं अधिक जटिल होंगी। इसलिए केवल राहत कार्यों पर आधारित व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी; जोखिम को पहले से कम करने वाली नीतियों पर अधिक बल देना होगा। साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की भूमिका निरंतर महत्वपूर्ण होती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन तथा वैश्विक जलवायु मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि भारत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि विश्व के लिए भी समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। विकासशील देशों की आवश्यकताओं और विकसित देशों की तकनीकी क्षमता के बीच भारत एक सेतु की भूमिका निभा सकता है।यदि भारत जलवायु-अनुकूल कृषि, हरित ऊर्जा, डिजिटल आपदा प्रबंधन और सतत शहरी विकास के सफल मॉडल प्रस्तुत करता है, तो वह वैश्विक दक्षिण के लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि बदलता मानसून और बढ़ती प्राकृतिक आपदाएँ हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते चेताने के लिए हैं।यह केवल मौसम का परिवर्तन नहीं,बल्कि विकास की दिशा बदलने का संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, बल्कि सह-अस्तित्व ही स्थायी प्रगति का आधार है। अब समय आ गया है कि भारत जलवायु परिवर्तन को केवल पर्यावरणीय मुद्दा न मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा,आर्थिक नीति,कृषि सुधार,शहरी विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व के केंद्र में रखे। यही दूरदर्शिता भारत को आने वाले दशकों में एक जलवायु-सुरक्षित, आपदा- प्रतिरोधी और सतत विकास की वैश्विक मिसाल बना सकती है। यही 21वीं सदी के भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है।

संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
9226229318

जींद से देश को मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन

लेखक- सौरभ वार्ष्णेय

भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। भारत अब जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन के बाद हाड्रोजन ट्रेन वाला आठवां देश बन जायेगा जिसका परीक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। हरियाणा के विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 जुलाई को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह केवल एक नई रेल सेवा की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत के हरित भविष्य, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता का प्रतीक भी है। हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के साथ भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिन्होंने स्वच्छ ईंधन आधारित रेल परिवहन को अपनाया है। जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, फ्रांस और स्वीडन जैसे विकसित देशों के बाद भारत हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक अपनाने वाला आठवां देश बनने जा रहा है। यह उपलब्धि भारत की बढ़ती तकनीकी दक्षता और नवाचार क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेगी।

क्या है हाइड्रोजन ट्रेन?- हाइड्रोजन ट्रेन ऐसी रेलगाड़ी होती है जो डीजल के स्थान पर हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करती है। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक के माध्यम से बिजली उत्पन्न की जाती है, जिससे ट्रेन संचालित होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पादन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता, बल्कि केवल जलवाष्प और पानी निकलता है। यही कारण है कि इसे पर्यावरण के अनुकूल और भविष्य की परिवहन प्रणाली माना जा रहा है। विश्व भर में बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय रेलवे भी वर्ष 2030 तक नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें हाइड्रोजन ट्रेनें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

भारतीय रेलवे के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि- देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के कोच चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्टरी (आईसीएफ) में तैयार किए गए हैं। इस परियोजना का सफल परीक्षण भी पूरा हो चुका है, जिससे इसके सुरक्षित और प्रभावी संचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। रेलवे विशेषज्ञों के अनुसार हाइड्रोजन ट्रेन पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक पर्यावरण-अनुकूल होने के साथ-साथ कम शोर उत्पन्न करती है। इसके संचालन से ईंधन आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी तकनीक को भी बढ़ावा मिलेगा।

यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

हरियाणा के विकास को मिलेगा नया आयाम- जींद से हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन का निर्णय हरियाणा के लिए भी विशेष महत्व रखता है। इससे प्रदेश की औद्योगिक, आर्थिक और तकनीकी पहचान को नई मजबूती मिलेगी। रेलवे अवसंरचना के विकास से क्षेत्र में निवेश की संभावनाएँ बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हरियाणा पहले से ही ऑटोमोबाइल, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल है। अब स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली के जुड़ने से राज्य आधुनिक तकनीक और हरित विकास का केंद्र बन सकता है।

डिजिटल क्रांति के दौर में बढ़ते साइबर अपराध, बड़ी चुनौती

लेखक - ललित गर्ग

डिजिटल क्रांति ने भारत को अभूतपूर्व गति, सुविधा और पारदर्शिता प्रदान की है। आज मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने सामान्य नागरिक के जीवन को सरल और सक्रिय बनाया है। भारत विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से उभर रहा है और 'डिजिटल इंडिया' तथा 'विकसित भारत-2047' का सपना इसी तकनीकी परिवर्तन पर आधारित है। किंतु इस उजले परिदृश्य के समानांतर एक भयावह अंधेरा भी तेजी से फैल रहा है-साइबर अपराधों का बढ़ता साम्राज्य। डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन वित्तीय ठगी, फिशिंग, पहचान की चोरी, निवेश घोटाले, व्यक्तिगत गोपनीयता पर सेंध, सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध, बाल यौन शोषण सामग्री का प्रसार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग आज केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक नैतिकता के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। विडंबना यह है कि जिस तकनीक का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को सुरक्षित, सुविधाजनक और ज्ञानसमृद्ध बनाना था, वही तकनीक अपराधियों के लिए सबसे प्रभावी हथियार बनती जा रही है। इंटरनेट की असीम संभावनाओं का लाभ जितनी तेजी से समाज ने उठाया है, उतनी ही तेजी से अपराधियों ने भी उसे अपने हित में ढाल लिया है। परिणामस्वरूप डिजिटल दुनिया में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है। डिजिटल व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है। जब कोई नागरिक मोबाइल पर क्यूआर कोड स्कैन करता है, यूपीआई से भुगतान करता है या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निवेश करता है, तब वह केवल तकनीक पर नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल तंत्र की विश्वसनीयता पर भरोसा करता है। यदि यही भरोसा लगातार साइबर ठगी, फर्जी कॉल, फिशिंग, नितांत व्यक्तिगत सूचनाओं के सार्वजनिक होने के भय, निवेश घोटालों और पहचान की चोरी जैसी घटनाओं से टूटने लगे, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर पड़ जाएगी। जिस प्रकार नकली मुद्रा का प्रसार पूरी आर्थिक व्यवस्था को संकट में डाल देता

है, उसी प्रकार डिजिटल धोखाधड़ी का बढ़ना कैशलेस अर्थव्यवस्था की अवधारणा को कमजोर कर सकता है। परंपरागत अपराधों और साइबर अपराधों में मूलभूत अंतर है। पहले अपराध किसी निश्चित क्षेत्र तक सीमित रहते थे, अपराधी की पहचान और गिरफ्तारी की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती थी। आज साइबर अपराधी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। उसके लिए जोखिम न्यूनतम और लाभ अधिकतम है। यही असंतुलन साइबर अपराध को अत्यंत खतरनाक बनाता है। अपराध का यह नया स्वरूप सीमाओं, भाषाओं और कानूनों की पारंपरिक सीमाओं को भी चुनौती दे रहा है। चिंता केवल आर्थिक अपराधों तक सीमित नहीं है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया मंचों पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के प्रचार-प्रसार के आरोपों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। यदि लोकप्रिय डिजिटल मंचों पर पैसे लेकर ऐसे विज्ञापन प्रसारित हो सकते हैं, तो यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक विफलता भी है। प्रश्न यह भी है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां केवल स्वयं को तकनीकी मंच कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती हैं? जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एल्गोरिद्म यह तय करते हैं कि कौन-सा विज्ञापन किस व्यक्ति तक पहुंचेगा, तब उन मंचों की जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। आज अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपत्तिजनक सामग्री हटाने का दावा करते हैं, किंतु व्यवहार में उनकी प्राथमिकता कई बार राजस्व और व्यावसायिक हित प्रतीत होती है। यदि बाल यौन शोषण, अश्लीलता, साइबर ठगी या संगठित अपराध से जुड़े विज्ञापन और सामग्री लंबे समय तक सक्रिय रह सकते हैं, तो यह केवल अपराधियों की सफलता नहीं, बल्कि डिजिटल मंचों की जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए बिना डिजिटल समाज स्वस्थ नहीं रह सकता। साइबर अपराध का सबसे दुखद पक्ष पीड़ित की मानसिक पीड़ा है। जीवनभर की बचत कुछ मिनटों में गायब हो जाती है। इसके बाद पुलिस, बैंक और साइबर हेल्पलाइन के चक्कर लगते हैं, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण अधिकांश मामलों में धन वापस नहीं मिल पाता। इससे नागरिक के भीतर व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। यदि अपराधी को दंड न मिले और पीड़ित को राहत न मिले, तो कानून का भय भी समाप्त होने लगता है। भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, हेल्पलाइन, साइबर क्राइम समन्वय केंद्र तथा डिजिटल सुरक्षा संबंधी अनेक पहलें शुरू की गई हैं। न्यायपालिका ने भी ऑनलाइन धोखाधड़ी को आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर गंभीर चिंता व्यक्त की है। फिर भी नीति और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच बड़ी दूरी दिखाई देती है। शिकायत दर्ज होने के बाद शुरुआती कुछ घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि इसी अवधि में बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएं और धन के प्रवाह को रोक दिया जाए तो बड़ी राशि बचाई जा सकती है। लेकिन अक्सर कार्रवाई में देरी अपराधियों के पक्ष में चली जाती है। डिजिटल सुरक्षा अब केवल पुलिस का विषय नहीं रही। यह आर्थिक नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा बहुआयामी प्रश्न बन चुकी है। विकसित देशों ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के समान महत्व दिया है।

धर्म का धन : श्रद्धा की अमानत, स्वार्थ का साधन नहीं

लेखक- श्रमण डॉ पुष्पेन्द्र

समाज की सबसे बड़ी शक्ति यदि कोई है, तो वह उसकी आस्था है। धन, सत्ता, ज्ञान और संसाधन समय के साथ बदल सकते हैं, परंतु जिस समाज की आस्था जीवित रहती है, वह समाज हर संकट से उबरने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि मंदिर, स्थानक, तीर्थ, उपाश्रय और धर्मस्थल केवल ईंट-पत्थरों से निर्मित भवन नहीं होते, बल्कि वे करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा, तप, त्याग और विश्वास के जीवंत केंद्र होते हैं। एक श्रद्धालु जब धर्मस्थल में प्रवेश करता है, तो वह केवल पूजा करने नहीं आता; वह अपने मन की व्यथा, आशा, कृतज्ञता और विश्वास भी वहीं अर्पित करता है। उसकी दक्षिणा केवल मुद्रा नहीं होती, बल्कि उसकी मेहनत की कमाई, उसके परिवार का विश्वास और धर्म के प्रति उसका समर्पण होता है। इसलिए धर्मस्थलों में आने वाला प्रत्येक अंश समाज की अमानत है। दुर्भाग्य तब उत्पन्न होता है, जब धर्म के नाम पर प्राप्त धन या संसाधनों का उपयोग धर्म के उद्देश्य से हटकर व्यक्तिगत लाभ, वैभव, प्रतिष्ठा या स्वार्थ के लिए होने लगे। यह केवल आर्थिक अनियमितता नहीं होती, बल्कि समाज की आस्था पर कुठाराघात होता है। जिस धन में हजारों श्रद्धालुओं की भावनाएँ जुड़ी हों, उसका दुरुपयोग केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि आत्मा और अंतरात्मा का भी विषय है। इतिहास साक्षी है कि धर्म का धन कभी किसी को स्थायी सुख नहीं दे पाया। जो संपत्ति छल, विश्वासघात या धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अर्जित होती है, वह बाहर से भले वैभव का प्रदर्शन करे, पर भीतर शांति नहीं दे सकती। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि अनुचित साधनों से प्राप्त धन अंततः विनाश का कारण बनता है। धर्म के धन के संदर्भ में यह बात और भी अधिक सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें केवल धन नहीं, असंख्य लोगों की श्रद्धा समाहित होती है। जैन दर्शन के चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने मानवता को संयम, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह का अमूल्य संदेश

दिया। इनमें अपरिग्रह का सिद्धांत विशेष रूप से आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। अपरिग्रह का अर्थ केवल अधिक वस्तुएँ न रखना नहीं है; इसका वास्तविक अर्थ है—लोभ, स्वार्थ, संग्रह की मानसिकता और अधिकार के दुरुपयोग से स्वयं को मुक्त करना। यदि धर्म से जुड़े व्यक्ति ही अपरिग्रह को भूल जाएँ और धर्म को संग्रह, प्रभाव या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का साधन बना लें, तो भगवान महावीर के संदेश का सार ही समाप्त हो जाता है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को बड़ा बनाना नहीं, बल्कि उसके अहंकार को छोटा करना है। धर्म हमें अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व सिखाता है; संग्रह नहीं, समर्पण सिखाता है; स्वार्थ नहीं, सेवा का मार्ग दिखाता है। धर्मस्थलों का निर्माण समाज के सहयोग से होता है। एक गरीब व्यक्ति अपनी छोटी-सी बचत से दान देता है, कोई किसान अपनी उपज का अंश अर्पित करता है, कोई व्यापारी अपनी आय का हिस्सा धर्मकार्य में लगाता है। सभी की भावना एक ही होती है—धर्म जीवित रहे, संस्कृति सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियाँ भी इन मूल्यों से जुड़ी रहें। ऐसे में यदि उस विश्वास को ठेस पहुँचती है, तो केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा समाज आहत होता है। आज आवश्यकता आरोप लगाने या विवाद बढ़ाने की नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि की है। धर्मस्थलों का संचालन पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी और उत्तरदायित्व के साथ होना चाहिए। आय-व्यय का स्पष्ट लेखा-जोखा, समाज के प्रति जवाबदेही और धर्म के उद्देश्य के अनुरूप संसाधनों का उपयोग—ये केवल प्रशासनिक व्यवस्थाएँ नहीं, बल्कि धार्मिक मर्यादाएँ हैं। समाज को भी यह समझना होगा कि धर्म की रक्षा केवल दान देने से नहीं होती, बल्कि धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने से होती है। जहाँ पारदर्शिता है, वहाँ विश्वास बढ़ता है; जहाँ विश्वास बढ़ता है, वहीं धर्म फलता-फूलता है। यदि कहीं त्रुटि दिखाई दे, तो उसका समाधान भी धर्मसम्मत, संयमित और संवादपूर्ण तरीके से होना चाहिए। कटुता, आरोप और वैमनस्य किसी भी धार्मिक वातावरण को शुद्ध नहीं बना सकते। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि व्यक्ति से बड़ा धर्म है, पद से बड़ी मर्यादा है और संस्था से बड़ी आस्था है। व्यक्ति बदल सकते हैं, व्यवस्थाएँ बदल सकती हैं, परंतु धर्म और उसकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रहनी चाहिए। यदि धर्म की पवित्रता सुरक्षित रहेगी, तो समाज का विश्वास भी अडिग रहेगा। भगवान महावीर का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा वैभव संग्रह में नहीं, त्याग में है; अधिकार में नहीं, उत्तरदायित्व में है; और बाहरी संपत्ति में नहीं, अंतःकरण की निर्मलता में है। यही संदेश आज प्रत्येक धार्मिक संस्था, प्रत्येक पदाधिकारी और प्रत्येक श्रद्धालु के लिए समान रूप से प्रासंगिक है। आइए, संकल्प लें कि धर्म को कभी स्वार्थ का साधन नहीं बनने देंगे। मंदिर, स्थानक और तीर्थ केवल भवन नहीं, हमारी आत्मा के प्रतीक हैं। उनकी पवित्रता, पारदर्शिता और मर्यादा की रक्षा करना हम सभी का नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है। जब धर्म शुद्ध रहेगा, तभी समाज सुदृढ़ रहेगा; और जब आस्था सुरक्षित रहेगी, तभी संस्कृति अमर रहेगी।

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के दिव्यांग क्रिकेट प्रमुख से मिले पूर्व राज्य आयुक्त उमा शंकर शर्मा, भारत में दिव्यांग क्रिकेट की तरक्की की और सार्थक कदम

लंदन / जयपुरः राजस्थान सरकार में दिव्यांगजन आयुक्तालय के पूर्व राज्य आयुक्त एवं दिव्यांगजन अधिकारों के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय उमा शंकर शर्मा ने इंग्लैंड की राजधानी लंदन मे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के दिव्यांग क्रिकेट प्रमुख इयान मार्टिन से मुलाकात कर भारत में दिव्यांग क्रिकेट के विकास एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की। शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान राजस्थान में दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा, उनके सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्रभावी क्रियान्वयन, सुगम्य वातावरण के निर्माण तथा दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड मे हुई इस बैठक के दौरान श्री शर्मा ने भारत में दिव्यांग क्रिकेट की वर्तमान स्थिति, खिलाड़ियों की प्रतिभा तथा उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत ने वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार अभिसमय का अनुमोदन किया तथा इसके अनुरूप दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 लागू किया गया, जिसके माध्यम से दिव्यांगजन के अधिकारों की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। श्री शर्मा ने विशेष रूप से दिव्यांग क्रिकेट को संस्थागत सहयोग, बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएँ और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। ईसीबी के दिव्यांग क्रिकेट प्रमुख के साथ हुई इस बैठक में भारत और ब्रिटेन के मध्य दिव्यांग क्रिकेट के विकास, खिलाड़ियों के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण तथा सहयोग के विभिन्न आयामों पर सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में चर्चा हुई की दिव्यांग क्रिकेट को भी मुख्यधारा के अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजनों में शामिल करने की के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर इयान मार्टिन ने कहा कि दिव्यांग क्रिकेट जैसे प्रयास न केवल खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, बल्कि समाज में समानता और सम्मान की भावना को भी मजबूत करते हैं।

उप्र में जन्मे विनायक शुक्ला बने ओमान पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान

मस्कट। ओमान क्रिकेट ने भारतीय मूल के विकेटकीपर-बल्लेबाज विनायक शुक्ला को पुरुष टीम का कप्तान नियुक्त किया है। टीम के उप-कप्तान रहे शुक्ला ने जतिंदर सिंह की जगह ली है, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में भारत में हुए आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ओमान की कमान संभाली थी। ओमान क्रिकेट ने विनायक शुक्ला को कप्तान इसलिए चुना है, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में टीम की तरक्की और सफलता में अहम भूमिका निभाई है। ओमान क्रिकेट ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नए कप्तान की घोषणा करते हुए कहा, 'एक नए अध्याय की शुरुआत। ओमान क्रिकेट गर्व के साथ विनायक शुक्ला को ओमान पुरुष क्रिकेट टीम का कप्तान घोषित करता है।' पिछले कुछ वर्षों में टीम की तरक्की और सफलता में अहम योगदान देने के बाद, 32 वर्षीय विनायक अब राष्ट्रीय टीम को अगले अध्याय में ले जाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

18 जून 1994 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे विनायक शुक्ला अपने कोच की सलाह पर बेहतर अवसरों की तलाश में साल 2021 में ओमान चले गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए 'नेशनल मेटल कैंस' में डेटा ऑपरेटर की नौकरी की। इसके साथ ही क्रिकेट खेलना भी जारी रखा।

विनायक ने 14 दिसंबर 2024 को टी20 मैच के साथ ओमान की तरफ से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया था। इसके बाद 10 फरवरी 2025 को एशिया कप में नामीबिया के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया। विनायक शुक्ला ओमान के पसंदीदा विकेटकीपर बने, उन्होंने खास तौर पर टी20 क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर से तेजी से रन बनाकर प्रभावित किया है। विनायक शुक्ला ने अपने करियर में 15 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 26 की औसत के साथ 312 रन बनाए। वहीं, 23 टी20 मुकाबलों में उनके बल्ले से 2 अर्धशतकों के साथ 447 रन निकले। विनायक 15 लिस्ट-ए मुकाबलों में 312 रन जोड़ चुके हैं।

टी20 सीरीजः जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान

वैभव-रिंकू को मौका

● सैमसन बाहर

मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एक बार फिर 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया है। तिलक वर्मा टीम के उप-कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ दो मुकाबलों की टी20 सीरीज का हिस्सा थे, लेकिन वहां उन्हें मौका नहीं मिल सका। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में भी वह प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं थे। आखिरकार, दूसरे मुकाबले में वैभव को मौका दिया गया, जिसके साथ 15 साल और 99 दिन की उम्र में वैभव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गए थे। हालांकि, अपने डेब्यू मैच में वैभव 14 रन ही बना सके थे। मैच फिनिशर रिंकू सिंह ने टी20 टीम में वापसी की है। इनके अलावा, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं। अशोक शर्मा ने आईपीएल 2026 में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से सुर्खियां बटोरी थीं। हर्ष दुबे और वरुण चक्रवर्ती को स्पिन गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल किया गया है, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर टीम का हिस्सा रहे अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को मौका नहीं दिया गया। विकेटकीपिंग का जिम्मा ईशान किशन और प्रभसिमरन सिंह को सौंपा गया है। संजू सैमसन इस सीरीज से बाहर हैं।

दोनों देशों के बीच 23, 25 और 26 जुलाई को हरारे स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टी20 सीरीज के तीनों मैच खेले जाने हैं।

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)।

चयन समिति ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में नितीश कुमार रेड्डी की जगह शिवम दुबे को शामिल किया है।

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बदलाव

रेड्डी की जगह दुबे टीम में शामिल

मुंबई। इंग्लैंड के खिलाफ 14 जुलाई से शुरू होने जा रही तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज से पहले चोटिल नितीश कुमार रेड्डी की जगह सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर शिवम दुबे को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। दुबे इंग्लैंड में जारी पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने सोमवार को कहा कि दुबे वनडे सीरीज के लिए भी वहीं रुकेंगे, क्योंकि रेड्डी अभी भी क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे हैं।

रेड्डी के रिहैबिलिटेशन के कारण उन्हें पहले ही आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और जिम्बाब्वे के विरुद्ध आगामी तीन मुकाबलों की सीरीज से बाहर कर दिया गया था। देवजीत सैकिया ने कहा, 'सिलेक्शन कमिटी ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में नितीश कुमार रेड्डी की जगह शिवम दुबे को चुना है।

भारत की अपडेटेड वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, शिवम दुबे।

व्यापार

लोग पैसे तो जमा कर रहे प्राइवेट बैंकों में और लोन ले रहे सरकारी बैंकों से

नई दिल्ली, एजेंसी। डिपॉजिट के मामले में प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों से आगे निकल गए हैं लेकिन लोन के मामले में एकदम उल्टी स्थिति है। क्रेडिट ग्रोथ के मामले में सरकारी बैंक प्राइवेट बैंकों पर भारी पड़ रहे हैं। 15 प्राइवेट और नौ सरकारी बैंकों के जारी किए गए शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में डिपॉजिट जुटाने के मामले में प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने सरकारी बैंकों को काफी पीछे छोड़ दिया। दोनों के बीच 3.6 प्रतिशत का अंतर रहा। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान प्राइवेट बैंकों के डिपॉजिट में पिछले साल के मुकाबले 14.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। दूसरी ओर सरकारी बैंकों में यह बढ़ोतरी 10.7 प्रतिशत रही। साफ है कि लायबिलिटी जुटाने में प्राइवेट बैंकों को लगातार स्ट्रक्चरल फायदा मिल रहा है।

मैक्वेरी कैपिटल में फाइनेंशियल सर्विसेज रिसर्च के हेड सुरेश गणपति ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में सरकारी बैंकों ने प्राइवेट बैंकों की तुलना में लोन (एडवांस) थोड़ी तेजी से बढ़ाए, लेकिन उनका डिपॉजिट बेस काफी कम था। इससे उनका कुल लोन-टू-डिपॉजिट रेश्यो पिछले साल के 77 प्रतिशत से बढ़कर 81 प्रतिशत हो गया। राम मंदिर केस में नया खुलासा, स्टेट बैंक ने 3 महीने पहले दान राशि गिनने वाले कर्मचारियों को बदलने की सिफारिश की थी

सरकारी बैंकों की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 28.8 प्रतिशत क्रेडिट ग्रोथ दर्ज की। बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट ग्रोथ 18.6 प्रतिशत और बैंक ऑफ बड़ौदा की 17.4 प्रतिशत रही।

प्राइवेट बैंकों का हाल

दूसरी ओर प्राइवेट बैंकों ने मजबूत क्रेडिट ग्रोथ के साथ-साथ बेहतर डिपॉजिट भी जुटाए। इससे उनका लोन-टू-डिपॉजिट रेश्यो 91 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 92 प्रतिशत हो गया। इससे प्राइवेट बैंकों की ग्रोथ बेहतर फंडेड लगती है। भले ही उनका लोन डिप्लॉयमेंट लेवल पहले से ही ऊंचा था। सरकारी बैंक लोन ग्रोथ बढ़ाने के लिए अपनी सरप्लस लिक्विडिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। गणपति ने कहा कि यह शॉर्ट-टर्म कमाई के लिए तो अच्छा है, लेकिन धीरे-धीरे उनके पुराने लिक्विडिटी कुशन को कम कर रहा है। डिपॉजिट में यह अंतर एक दशक से चल रहे स्ट्रक्चरल बदलाव को दिखाता है। इस दौरान सरकारी बैंकों का डिपॉजिट मार्केट शेयर लगातार कम हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के आखिर में यह 76 प्रतिशत था जो मार्च 2026 में घटकर 57 प्रतिशत रह गया।

एलपीजी संकट ने बदली लोगों की खाना बनाने की हैबिट, सिलेंडर को अब नहीं मिल रहा ज्यादा भाव!

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम एशिया में हालात ठीक होने के साथ ही अब भारत में भी एलपीजी की सप्लाई सामान्य हो रही है। लेकिन इस संकट ने कुछ लोगों की खाना बनाने की आदतों को हमेशा के लिए बदल दिया है। वे अब इंडक्शन कुकिंग को अपना रहे हैं। कुछ लोग एलपीजी के साथ-साथ इंडक्शन कुकिंग का हाइब्रिड मॉडल अपना रहे हैं। भारी मांग को देखते हुए घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियां इंडक्शन कुकटॉप का प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कैटगरी में अब कई नई कंपनियां आ रही हैं जबकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पर बढ़ी हुई मांग का भारी दबाव है। जुलाई-सितंबर तिमाही के ऑर्डर पिछले साल के मुकाबले कम से कम दोगुने हैं। इसका मार्केट 2025 में लगभग 40 लाख यूनिट था। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस साल यानी 2026 में यह लगभग 70 लाख यूनिट तक पहुंच जाएगा। जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए इंडक्शन कुकटॉप के ऑर्डर बहुत ज्यादा हैं और प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले दोगुना है।

टॉप गेयर में मार्केट, जमकर लोन बांट रहे बैंक, गाड़ियों की रेकॉर्ड बिक्री

नईदिल्ली, एजेंसी। ईरान-अमेरिका तनाव और होर्मुज संकट के बीच भारत के ऑटोमोबाइल डीलर असोसिएशन का महासंघ अगर ये बताए कि इस दौरान लोग रेकॉर्ड संख्या में कार और बाइक खरीद रहे हैं तो इसे कैसे समझा जाए। समझदार लोग तो यही कह रहे हैं कि क्राइसिस जेनुइन है। अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण तेल और गैस की सप्लाई पर असर हुआ है। मंदी की आशंकाएं जताई जा रही हैं। सप्लाई चेन पर असर हुआ है। भारत में विपक्ष के एक बड़े नेता ने तो यहां तक कहा है कि इस संकट के कारण आर्थिक सुनामी आने वाली है और सरकार के अंतिम दिन शुरू हो गए है

आनंद महिंद्रा की बड़ी भविष्यवाणी, बोले- बदलती दुनिया में भारत बनेगा भरोसेमंद कनेक्टर इकोनॉमी

नई दिल्ली, एजेंसी। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा है कि आज की बिखरी हुई दुनिया में भारत वैश्विक बाजारों, सप्लाई चेन और भू-राजनीतिक गुटों को जोड़ने वाली एक भरोसेमंद कनेक्टर इकोनॉमी के रूप में उभर सकता है। सोमवार को शेयरधारकों के नाम लिखे अपने पत्र में उन्होंने यह बात कही।

आनंद महिंद्रा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक ताकत, रणनीतिक स्थिति और बढ़ती साख उसे नए उभरते वर्ल्ड ऑर्डर के केंद्र में रखती है। आनंद महिंद्रा ने मौजूदा वैश्विक स्थिति को 'मंथन 2.0' का नाम दिया, जहां अनिश्चितता अब कोई अपवाद नहीं बल्कि एक नियम बन चुकी है। महिंद्रा ग्रुप का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

यह रिपोर्ट महिंद्रा ग्रुप के अब तक के सबसे मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के बाद आई है। वित्त वर्ष 2026 में ग्रुप ने रिकॉर्ड प्रदर्शन दर्ज किया। यह इस प्रकार रहाः बिजनेस लीडरशिपः स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स की बिक्री में 20 प्रतिशत की ग्रोथ रही, ट्रैक्टर की बिक्री 5 लाख यूनिट के पार निकल गई और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट में कंपनी ने 40 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ अपना दबदबा बनाए रखा।

बदलावों की ओर बढ़ रही दुनिया

उन्होंने कहा कि दुनिया अब वैश्विक झटकों से स्थायी बदलावों की ओर बढ़ रही है। ऐसे में जो देश या कंपनियां लचीलेपन के साथ तेजी से कदम बढ़ाएंगी, वही आगे निकलेंगी। भारत अब गुटनिरपेक्ष से एक बहु-संरेखित ताकत और भरोसेमंद पार्टनर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने महिंद्रा ग्रुप की रणनीति के बारे में भी बात कही।

भविष्य की ग्रोथ के लिए एआई पर दांव

महिंद्रा ग्रुप के सीईओ और एमडी डॉ. अनीश शाह ने अपने पत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य की विकास रणनीति का मुख्य स्तंभ बताया। शाह के मुताबिक महिंद्रा उन चुनिंदा भारतीय कंपनियों में से है जो ढ्ढ का इस्तेमाल सिर्फ किसी एक विभाग तक सीमित न रखकर पूरे संगठन में बड़े पैमाने पर कर रही है। इसका उपयोग ऑपरेशन्स को बेहतर बनाने, रणनीतिक फैसले लेने और ग्राहकों के अनुभव को शानदार बनाने के लिए किया जा रहा है।

टाटा को 18000 करोड़ का घाटा, सुबह-सुबह कंपनी से मिली बैड न्यूज, जूडियो और वेस्टसाइड से कनेक्शन

नई दिल्ली, एजेंसी। टाटा ग्रुप की फैशन रिटेलर कंपनी ट्रेंट लिमिटेड को मंगलवार सुबह बड़ा झटका लगा। कंपनी के शेयर में करीब 11 फीसदी की गिरावट आई। इस गिरावट के कारण कंपनी का मार्केट कैप करीब 18 हजार करोड़ रुपये कम हो गया। यह गिरावट ऐसे समय आई है, जब पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू बाजार के अनुमानों से कम रहा। ट्रेंट लिमिटेड वेस्टसाइड और जूडियो जैसी लोकप्रिय चेन चलाती है। मंगलवार को इस कंपनी के शेयर में जबरदस्त बिकवाली देखी गई। मंगलवार सुबह यह शेयर गिरावट के साथ 3,111 रुपये पर खुला। इसके बाद इसमें और गिरावट आती गई। सुबह 10:30 बजे यह शेयर करीब 11 प्रतिशत गिरकर 2,976.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कैसा रहा है शेयर का प्रदर्शन ट्रेंट का शेयर पिछले एक महीने में 23 प्रतिशत और मार्च 2026 के अपने निचले स्तर से 50 प्रतिशत तक चढ़ चुका था। निवेशक उम्मीद कर रहे थे कि वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही की 20 प्रतिशत विकास दर के मुकाबले इस तिमाही में और तेजी आएगी, लेकिन इसके विपरीत रफ्तार धीमी पड़ गई। ट्रेंट का पहली तिमाही का स्टैंडअलोन रेवेन्यू सालाना आधार पर 19 प्रतिशत बढ़कर 5,666 करोड़ रुपये रहा, जो बाजार के 22 प्रतिशत ग्रोथ के अनुमान से कम था। सालाना आधार पर कुल स्टोर्स की संख्या में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, लेकिन प्रति स्टोर रेवेन्यू में लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह संकेत देता है कि नए स्टोर्स से कमाई धीमी हो रही है या पुराने स्टोर्स के ग्राहकों में ही बंटवारा हो रहा है। जून तिमाही में कंपनी ने 26 नए फैशन स्टोर जोड़े, जिससे कुल संख्या 1,312 हो गई है। इसमें से जूडियो ने 19 नए स्टोर जोड़कर 982 का आंकड़ा छुआ, जबकि वेस्टसाइड ने सिर्फ 1 नया स्टोर जोड़ा और वह 301 पर पहुंचा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593 RNI No.: DELHIN/2008/23928
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)